प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है

रवींद्रनाथ ठाकुर

वर्ष-04, अंक - 33 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 19 मई 2022 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सहेली के पति ने घर में किया हाथ साफ

भोपाल। एक महिला पति के साथ अपनी सहेली से उसके घर मिलने गई थी जहां उसने उसे अपने जेवर दिखाए थे। अगले ही दिन महिला के घर से जेवर चोरी हो गए और चोरी करने वाला कोई नहीं बल्कि सहेली का पति निकला। उसने पत्नी की सहेली के घर रात को सेंध लगाकर चोरी की।

यह मामला भोपाल के गांधी नगर का है। यहां ममता रघुवंशी नाम की महिला ने दो लाख के जेवर अपने घर से चोरी होने की रिपोर्ट गांधी नगर थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि विजय ठाकुर और उसका साथी रवि कुशवाह जेवर बेचने के लिए घूम रहे हैं। इन लोगों को पुलिस ने चोरी का सामान बेचने के संदेह में हिरासत में लेकर जेवरात के बारे में पूछताछ की तो वह उनके नहीं बल्कि चोरी के निकले।

सेंध लगाकर वारदात को दिया अंजाम

गांधी नगर पुलिस ने जब रवि और विजय से पूछताछ की कि, ममता रघुवंशी के जेवर होने की बात सामने आई। विजय ने पुलिस को बताया कि, उसकी पत्नी ममता की सहेली थी और वह पत्नी के साथ वारदात के पहले मिलने गया था। वहां ममता ने उसकी पत्नी को अपने जेवर दिखाए थे। इसके बाद एक रात उसने ममता रघुवंशी के घर पर वारदात की और जेवर चुरा लिए थे।

हनुमान मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद, कलेक्टर-एसपी ने शहर में निकाला मार्च

नीमच।

शहर की पुरानी कचहरी क्षेत्र में सोमवार रात दो समुदायों में विवाद हो गया। दरगाह के समीप की भूमि पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर यह स्थिति बनी। इस दौरान कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी मची। दोनों पक्ष आमने-सामने हुए और पथराव हुआ। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, बाइक में भी आग लगा दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भांजीं। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में हो पाई। प्रशासन ने हालात को देखते हुए नीमच सिटी क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। मामले में पथराव, आगजनी व तोड़फोड़ को लेकर अभी तक चार अपराध पंजीबद्ध कर नौ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है एवं अन्य आरोपितों को चिन्हित किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति सामान्य होकर नियंत्रण में है। संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन कैमरा एवं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सभी गतिविधियों पर सतत निगाह रखी जा रही है। सोमवार शाम दरगाह के समीप कुछ लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाही तो दूसरे पक्ष ने आपत्ति ली थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। उस समय समझाइश के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन करीब साढ़े 7 बजे बाद यह विवाद गहरा गया। इस दौरान दोनों समुदायों के लोग एकत्र हो गए।

कलेक्टर-एसपी ने निकाला मार्च

नीमच सिटी मे स्थिति तनावपूर्ण हालात देख शहर के सभी पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया था। स्थिति नियंत्रित होने और हंगामा शांत होने के बाद कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी सूरजकुमार वर्मा ने विवाद वाले क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला और दोनों पक्षों के लोगों से संयम बरतने को कहा।

बंद हुआ शहर का बाजार

नीमच शहर में जैसे ही विवाद की खबर फैली, देखते ही देखते नीमच में दुकानों के शटर गिर गए और पूरा बाजार बंद हो गया। हालात देख पुलिस ने भी लोगों को घरों के अंदर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की। रात्रि साढ़े 9 बजे बाद नीमच सिटी के हालात ऐसे हो गए थे, जैसे कफ्यू लग गया हो। एसपी सूरज कुमार वर्मा ने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द, शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जनता से अपील की है कि, पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना किसी अनुमति के एक स्थान पर एकत्रित न हों। किसी भी प्रकार की रैली, कार्यक्रम, जुलूस, चल समारोह, धरना, सभा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, इंटरनेट मीडिया, पोस्टर, बैनर या अन्य किसी माध्यम से भ्रामक प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

नगरीय निकाय चुनाव में लागू होगा ओबीसी आरक्षण

नई दिल्ली।

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। यह आदेश बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को शिवराज सरकार की जीत बताया जा रहा है। भाजपा ने इसकी अपनी जीत बताई है तो कांग्रेस ने कहा है कि, यह कोई नई बात नहीं है बल्कि अदालत ने पुराने 14 फीसदी आरक्षण को रखा है।

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की विस्तृत रिपोर्ट को अदालत ने देखने के बाद यह फैसला किया है। अदालत ने कहा कि, किसी भी परिस्थिति में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही एक सप्ताह में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, सत्य की जीत हुई है। आज का दिन ऐतिहासिक है। हमने यही कहा था कि, हम चुनाव चाहते हैं और ओबीसी आरक्षण के साथ। चौहान ने कहा कि, कांग्रेस ने पाप किया था। कांग्रेस के लोग ही सुप्रीम कोर्ट गए थे उसके कारण ही ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। सीएम ने कहा कि, उनकी सरकार ने हर संभव प्रयास किया और ओबीसी कमीशन बनाया। उसने व्यापक सर्वे किया और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाई वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की।

सीएम चौहान ने कहा कि, कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड़यंत्र करते रहे, कभी ओबीसी को न्याय देने की उनकी नीयत नहीं थी। कमलनाथ पर पलटवार किया कि, जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी दिया था तो तब अदालत में क्यों सही स्थिति नहीं रखी जिससे कोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब ओबीसी को न्याय मिला है।

किसानों के आगे झुकी पंजाब सरकार

चंडीगढ़।

पंजाब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को किसानों का आंदोलन तेज हो गया था और 23 संगठनों से जुड़े किसान चंडीगढ़ के लिए कूच कर गए थे, जिन्हें मोहाली में रोक लिया गया था। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने धान रोपाई की मांग स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत 7 जून से इसके पहले चरण की शुरुआत होगी। पंजाब सरकार ने तीन चरणों में धान रोपाई की मांग को स्वीकार कर लिया है। भगवंत मान ने बुधवार को दोपहर को किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वहीं बड़ी संख्या में किसान चंडीगढ़ की सीमा पर ही डटे हुए हैं और सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी किए जाने के बाद ही पीछे हटने की बात कही है।

होगी धान की रोपाई

दरअसल पंजाब सरकार ने ऐलान किया था कि, धान की रोपाई का सत्र 18 जून से शुरू किया जाए और पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होनी चाहिए। इस पर किसानों ने आपत्ति जताई थी। अब यह तीन चरणों में होगी और 7 जून से इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले राउंड में उन क्षेत्रों में धान की रोपाई होगी, जहां पानी की कमी है। इसके बाद 14 और 17 जून को दूसरे एवं तीसरे चरण की शुरुआत होगी। किसानों से मुलाकात में भगवंत मान ने मूंग की फसल को भी एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया। इसके लिए मंडियों का भी चयन कर लिया गया है और जल्दी ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस से किया इनकार

किसानों संग बैठक में भगवंत मान ने कहा कि, वह बासमती की खरीद के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे और उसके मुताबिक ही फैसला लेंगे। मक्के की खरीद पर भी जल्दी ही फैसला लेने का भरोसा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने गेहूं की प्रति क्विंटल खरीद पर 500 रुपए का बोनस दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया। कहा जा रहा है कि, अब जल्दी ही किसान धरने से उठने पर फैसला ले सकते हैं। सीएम से मुलाकात के बाद प्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचेंगे और साथी नेताओं से बातचीत के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।

त्रि-'स्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे, चुनाव आयोग ने जारी किये निर्देश

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 3 चरणों में मतदान करवाने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने मतदान की दिनांक घोषित नहीं की है लेकिन 3 चरणों में किस विकासखंड में पहले चरण में मतदान होगा व किस विकासखंड में दूसरे व तीसरे चरण में मतदान होगा का आदेश जारी किया गया है। जिसमें प्रदेश के कुल 52 जिलों के 85 विकासखंड में पहले चरण के अंतर्गत चुनाव करवाया जाना है। वही दूसरे चरण में 110 विकासखंड में व तीसरे चरण में 118 विकासखंड में चुनाव करवाया जाना है। उक्त आदेश से यह साफ होता है कि, अब जल्द ही मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिसकी तेयारी चुनाव आयोग द्वारा शुरू कर दी गई है।

ताजमहल के फव्वारे बंद हो-ओवेसी

नई दिल्ली।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, इस सप्ताह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया 'शिवलिंग' वास्तव में एक 'फव्वारा' है और घोषणा की कि अगर इसे जांच के बाद शिवलिंग माना लिया जाता है, तो 'ताजमहल के सभी फव्वारे बंद होने चाहिए। इसके अलावा ओवैसी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश को 1990 के दशक में वापस ले जाना चाहती है जब दंगे हुए थे।

ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपनी टिप्पणी को भी रेखांकित किया, जिसमें कहा गया था कि, मुसलमानों को धर्म पालन की अनुमति है। जिसका मतलब है कि, वे मस्जिद में नमाज अदा करने से पहले वुजू कर सकते हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला दिया।अदालत ने कहा कि, जिस स्थान पर 'शिवलिंग' मिला है, उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के डीएम को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान की सुरक्षा की जाए, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। नजीब जंग के बाद वह दिल्ली के एलजी बने थे। उन्हें दिसंबर 2016 में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रशासन को लेकर अकसर उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेद रहते थे।

30 दिसंबर 2021 को बैजल का कार्यकाल पूरा हो गया था लेकिन उन्हें सेवा में विस्तार दिया गया था। वह पांच वर्ष तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। अधिकारों को लेकर भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच विवाद होता रहा है।

लोकसभा चुनाव 2024: पीएम मोदी ने दिए सुझाव, एक्शन में योगी

लखनऊ, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे के दौरान दिए गए मंत्र का असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के दिए गए मंत्र को लागू करने के प्रदेश का अलग-अलग सेक्टर के हिसाब से विकास करने का पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है। इसके अलावा प्रदेश के पिछड़े जिलों के अलावा पिछड़े विकास खंडों की भी पूरी जानकारी इकट्ठा कर विकास कार्य की योजनाओं को बहुत जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के दिए गए मंत्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी पिछड़े जिले और सभी पिछड़े विकास खंडों में योजना के तहत विकास किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंचेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल से लौटने के बाद लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट के साथ विस्तार से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान मंत्री समूह को उत्तर प्रदेश के सभी पिछड़े जिलों के कस्बों, तहसीलों, शहर और गांवो के विकास का एक पूरा ढांचा तैयार कर उसको योजनाबद्ध तरीके से सिरे चढ़ाने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के अगले दिन ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के आला अफसरों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री की नसीहत को तत्काल प्रभाव से अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए।

उत्तर प्रदेश में विकास की सभी योजनाओं को 10 सेक्टर में बांट कर उनकी लगातार मॉनिटरिंग करने का दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपने मंत्रियों को 100 दिन का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को कहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की योजनाएं न रुकें, इसके लिए तीन महीने से लेकर छह महीने और फिर एक साल के बाद दो साल तक का पूरा रोडमैप तैयार कर उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं।

राजीव गांधी के हत्यारे को मिली रिहाई

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिहा किए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि, नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे हालात पैदा किए कि अदालत को यह निर्णय देना पड़ा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आतंकवाद को लेकर सरकार का यह रवैया निंदनीय है। उन्होंने मीडिया से कहा, उच्चतम न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे करोड़ों भारतीय नागरिकों की भावना आहत हुई है क्योंकि न्यायालय ने राजीव गांधी जी के एक हत्यारे को रिहा कर दिया है। तथ्य बड़े स्पष्ट हैं और जिम्मेदार मोदी सरकार है।

उनके अनुसार, 9 सितंबर 2018 को तमिलनाडु की तत्कालीन अन्नाद्रमुक-भाजपा सरकार ने उस समय के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को सिफारिश भेजी कि राजीव गांधी जी की हत्या के सभी सात दोषियों को रिहा कर दिया जाए। राज्यपाल ने कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए मामला राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति ने भी कोई निर्णय नहीं लिया।

सुरजेवाला ने दावा किया कि, इस विलंब और भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण एक हत्यारे को रिहा कर दिया। अब सभी दोषी रिहा हो जाएंगे।

गौरतलब है कि, उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया, जो उम्रकैद की सजा के तहत 30 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया।

45 डिग्री में बिना पंखे और पानी के काम करने पर मजबूर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका

चार आंगनवाडियों में बिजली मीटर तक नहीं, सात उप आंगनबाड़ी किराये से संचालित

माही की गूंज , बामनिया। गौरव भंडारी

स्वास्थ्य सेवाओं और नो निहालो को प्रारंभिक शिक्षा के साथ मातृत्व समय से निकलने वाली माताओं के लिए शासन ने आंगनवाड़ी के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही रही है, लेकिन सुविधाओं के आभाव में आगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ-साथ आशा कार्यकर्ताओं को भी कार्य करने में परेशानी का सामना किया। यहां टंकी मोहल्ला स्थित आंगनवाड़ी पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए नियमित होने वाले टीकाकरण के दौरान बड़ी समस्या सामने आने के बाद जब नगर की सारी आगनवाड़ियो की स्थिती देखी गई, तो विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई।

बिना बिजली-पानी 45 डिग्री तापमान में कार्य करने पर मजबूर

बात करे नगर की तो पूरी पंचायत में कुल 4 आगनवाड़ी और 7 उप आंगनवाडी है। जिसमे से केवल 4 आगनवाड़ी भवन टंकी मोहल्ला, गवली मोहल्ला, काजलिया और चित्तौड़ी फलिये में भवन बने हुए है। बाकी 7 उप आंगनवाडी किराए के भवन में संचालित या यूं कहें आगनवाडी सहायिका के घर से ही संचालित हो रहे है। जो चार आंगनवाडी भवन बने हुए है उन चारों में बिजली की व्यवस्था के लिए लाइन भी डाली हुई है लेकिन न तो आंगनवाडियों में बिजली के सामान पंखे, बल्ब आदि लगे हुए है, न ही विभाग ने यहां मीटर कनेक्शन लिया हुआ है जिससे यहां काम करने वाली कार्यकर्ता और सहायिका को इस भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान में कार्य करना पड़ रहा है। टीकाकरण सहित अन्य जानकारी व लाभ के लिए आने वाली महिलाओं और बच्चों को भी इस गर्मी में बैठना पड़ता है ।

आगनवाड़ियो में पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था नही है। इन भवनों पर टंकी और पाईपलाईन बिछा दी गई, लेकिन उसमे पानी कैसे पहुचे इसकी कोई व्यवस्था नही है। कई जगह पर होल खोदे गए, लेकिन बिजली कनेक्शन के अभाव में उनको भी नही चलाया जा सकता। जिससे यहां कार्यकर्ता, कर्मचारियों और छोटे बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। आगनवाडियो पर लगी पाइपलाईन और टंकी सरकारी योजनाओं का मुह चिढ़ाती दिख रही है।

परियोजना अधिकारी इशिता मसानिया से इस विषय मे चर्चा की तो, उनको आगनवाड़ी में बिजली कनेक्शन होने की कोई जानकारी नही है या यूं कहें कि, उनके हिसाब से आगनवाडियो में बिजली कनेक्शन हैं। साफ है मेडम अपने कार्य की इतिश्री ऑफिस के केबिन में बैठ कर करती है और जमीनी हकीकत से कोसो दूर है। इधर मुख्यमंत्री मैदान में रहने वाले अधिकारियो के साथ काम करने की बात कर रहे, वही दूसरी और अधिकारी मुख्यालय पर बैठकर कागजी खानापूर्ति कर रहे है।

आगामी चुनाव हेतु श्री भूरिया ने ली समीक्षात्मक बैठक

माही की गूंज,झाबुआ।

आगामी नगरपालिका परिषद के होने जा रहे चुनाव को मददेनजर रखते हुए, झाबुआ विधायक एवं पूर्व केन्द्रिय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अपने कार्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक रखी। जिसमे नगर की प्रमुख समस्याओं तथा पालिका द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो की समिक्षात्मक बैठक कर उपस्थित कांग्रेसजनों तथा कांग्रेस समर्थित पार्षदों एवं नगरपलिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को नगर के हित में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वीत करते हेतु आवश्यक निर्देश दिये। मुख्य नगरपालिका अधिकारी एल.एस डोडिया तथा पालिका के सब इंजिनियर धीरेन्द्र रावत से जानकारी प्राप्त कर विकास कार्यों की समिक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये ।

इस अवसर पर श्री भूरिया ने सर्वानुमति से वरिष्ठ अभिभाषक रमेश डोशी को झाबुआ नगरपालिका के चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। जो आगामी चुनाव हेतु नगर के विभिन्न वार्डों कां सर्वे कर योग्य प्रतियाशियों के चयन में समिति का गठन कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। 15 दिवस के अंतराल में अपनी रिपोर्ट, जिला कांग्रेस तथा विधायक श्री भूरिया को भी इससे अवगत कराएंगे। श्री डोशी के इस नियुक्ति पर प्रदेश व कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया तथा जिला कांग्रेस निर्मल मेहता ने पुष्प मालाओं से स्वागत किया।

बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता ने नगरपालिका चुनाव की रणनीति प्रस्तुत करते हुए, लोगों में जनाधार वाले उम्मदवारों पर जोर देते हुए, 55 हजार की आबादी वाले झाबुआ नगर के नेतृत्व में सब का विश्वास अर्जित करने वाले व्यक्ति को प्रमुखता दिये जाने पर प्रकाश डाला। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने जोर देते हुए कहा कि, नगरपलिका के चुनाव में युवकों के साथ जनाधार वाले अनुभवी व्यक्तित्व को भी परिषद के आगामी चुनाव में महत्व दिया जायेगा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष रूपसिंह डामोर, हेमचन्द डामोर, पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा, शांतिलाल पडियार, प्रवक्ता द्वय आचार्य नामदेव, साबिर फिटवेल, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती मन्नु डोडियार, आशिष भूरिया, प्रकाश रांका, मालुबेन डोडियार, धुम्मा डामोर, हेमेन्द्र कटारा, रसिद कुरेशी, शायरा बानो, मनिष व्यास, सामाजिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बापूसिंह कटारा, सुनिल भूरिया, संजय परमार, गोपाल शर्मा, वरूण मकवाना, एनएसयुआई जिला अध्यक्ष विनय भाबोर, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय भाबोर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गोरव सक्सेना, वसीम सैयद, कैलाश डामोर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष काना गुण्डिया, जनपद सदस्य पेमा भाबोर, आदि कांग्रेसजन उपस्थित थे।

समस्या: पटवारियो ने तहसीलदारो को सौपा ज्ञापन

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आव्हान पर जिले की समस्त तहसीलों में पटवारियों को आने वाली विधिक व्यावहारिक समस्याओं को लेकर पटवारियो ने प्रमुख् सचिव राजस्व और आयुक्त भू अभिलेख म.प्र. के नाम तहसीलदारो को ज्ञापन सौंपे गए ।

मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष अखिलेश मुलेवा ने बताया कि, प्रदेश में पटवारियों को विभिन्न कार्यों में हो रही व्यावहारिक समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने हेतु आठ बिंदूओ पर ज्ञापन प्रदेश के साथ जिले की समस्त तहसीलों में तहसीलदारो को प्रमुख् सचिव राजस्व और आयुक्त भू अभिलेख के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गए। श्री मुलेवा ने बताया कि, पटवारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा उनकी एक भी मांग को गंभीरता से सुना नहीं गया है। आज दिनांक तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। पटवारी के कार्यों का यदि ईमानदारी से जमीनी स्तर पर सर्वे किया जाए तो ग्रामीण स्तर पर पटवारी ही सबसे ज्यादा कार्य करते हैं। पटवारियों को इतना अधिक कार्य करने के उपरांत भी जीवनकाल में कोई पदोन्नति नहीं दी जाती। पटवारी जिस पद पर पदस्थ होता वहीं से सेवानिवृत्त हो जाता है। पटवारियों की सी.आर. नही लिखी जाती है और ना ही समयमान वेतनमान का लाभ यथा समय दिया जा रहा है। पटवारियों को समस्या/समीक्षा बैठक के नाम पर आए दिन ऑफिसों में बैठाए रखा जाता है। पटवारी दिनभर फील्ड का काम करें एवं शाम को समीक्षा बैठक में उपस्थित हो। पीएम किसान एवं सीएम किसान सम्मान निधि पटवारियो के गले की फांस बन के रह गई है। इस योजना में नित नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं, और पटवारी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रतिवर्ष आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं फोटो सत्यापन कराया जा रहा है। इस प्रकार पटवारियों का शोषण हो रहा है। स्वामित्व योजना बीपीएल जांच एवं खाद्य पर्ची मुख्यमंत्री आवास विकास योजना, वर्षा मे दो बार फसल गिरदावरी और अब जायद गिरदावरी को सम्पूर्ण प्रदेश मे लागू कर दिया है। सीएम हेल्पलाइन ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पटवारी मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित हो रहे हैं, और इस प्रताड़ना से हमारे 30 से अधिक साथी दुर्घटनाओं शिकार होकर दिवंगत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं अन्य आपातकालीन सेवा में पटवारियों को लगा दिया जाता है। जो अपने घर परिवार को छोड़कर ड्यूटी में लगे रहते हैं। कई पटवारी साथी तनावग्रस्त होकर अवसाद की स्थिति में चले गए है। पटवारियो ने मांग की है कि, उनकी न्यायोचित मांगों पर शासनस्तर से गंभीरता पूर्ण विचार करने एवं पटवारियों को मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सप्ताह में 5 दिन कार्यालय समय में कार्य करने हेतु निर्देश प्रसारित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में मध्यप्रदेश के पटवारी 1 जून से आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर कार्यालयीन समय में ही कार्य करेंगे एवं इसके लिए शासन-प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे।

पटवारी संघ के प्रांतीय आवाहन पर बुधवार को जिले की तहसीलों में तहसील अध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार पेटलावद ,मलसिंह डामोर थांदला, आनंद मेला मेघनगर ,गोपाल जोशी राणापुर ,छतर सिंह रावत रामा एवं तहसील झाबुआ मे नानूराम मेंरावत के साथ गोविन्द हाडा ठाकुर सिह भूरिया, निलेश पाटीदार, आलोक निनामा, नब्बूसिंह डामोर, पूजा ओसारी, नेहा राठौर, अंजलि कटारा, हेमलता बामनिया, करणसिंह बामनिया ने तहसीदार आशीष राठौर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बडी संख्या मे पटवारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री चौहान ने किया मिशन नगरोदय का शुभारंभ

जिला स्तरीय कार्यक्रम नगरपालिका परिसर में हुआ

माही की गूंज, झाबुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भोपाल से मिशन नगरोदय का वर्चअली शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा इस दौरान 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से भूमि-पूजन, लोकार्पण, गृह-प्रवेश और हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से राशि वितरण की गई। इसके साथ ही अमृत-2.0 में 12 हजार 858 करोड़ 71 लाख और स्वच्छ भारत मिशन-2.0 में 4 हजार 913 करोड़ 74 लाख रुपये की योजनाओं का भी शुभारंभ किया।

नगरपालिका द्वारा स्थानीय कार्यक्रम नगरपालिका परिषद झाबुआ परिसर में 17 मई को सायं 6 बजे से प्रारंभ किया गया। यहां पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा, नगरपालिका अध्यक्ष मन्नू बैन डोडियार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एलएन गर्ग, नगरपालिका उपाध्यक्ष रोशनी डोडियार, सम्माननीय पार्षद, गणमान्य नागरिक, जिला आपूर्ति अधिकारी मुकुल त्यागी, जिला पंचायत से एमडीएम प्रभारी रावत एवं रमेश भूरिया, शिक्षकगण, योजनाओं के हितग्राही आदि उपस्थित थे। जहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को निःशुल्क मूंग का वितरण कर शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा, नगरपालिका अध्यक्ष मन्नु बैन डोडियार, नगरपालिका उपाध्यक्ष रोशनी डोडियार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत कुपोषण दूर करने के लिए शासन द्वारा माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को 15 किलो एवं प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 10 किलो मूंग का वितरण किया गया। योजना में जिले के 2379 स्कूलों के 195000 छात्रों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसकी व्यवस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम के माध्यम से वितरण किया गया है। जनपद स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर वितरण करने हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मॉनिटरिंग के लिए फोटो ग्राफी, वीडिया ग्राफी करवाई गई है। नगर पालिका परिसर झाबुआ में प्रतिकात्मक रूप से मूग का वितरण किया गया। जिसमे शा.कन्या.मा.वि.बस स्टैण्ड झाबुआ की 05 छात्राएं, शा.मा.वि.हुडा के 05 छात्र, शा. मा. वि. बाल मंदिर झाबुआ की 06 छात्राओं को मूग वितरण किए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 10 हितग्राहियों को किस्त की राशि प्रतिकात्मक रूप से नगरपालिका परिसद झाबुआ में प्रदान की गई। इसी तरह प्रधानमंत्री स्वनीधि योजना के अंतर्गत 07 हितग्राहियों को बीस-बीस हजार प्रतिकात्मक रूप से दिए गए। यह राशि उनके खाते में सिधे जमा होगी। इसी तरह प्रधानमंत्री स्वनीधि योजना में बीस-बीस हजार रुपये की स्वीकृति आदेश 10 हितग्राहियों को दिए गए। प्रधानमंत्री स्वनीधि के अंतर्गत 1 लाख 40 हजार का वितरण किया गया एवं 2 लाख की स्वीकृति स्वनीधि योजना में जारी की गई।

दो साल बाद आयोजित हो रहा चांदशाह-गुलाबशाह वली का उर्स

आज जुलूस के साथ होगा चार दिवसीय उर्स का आग़ाज़

माही की गूंज, झाबुआ।

शहर के मेहताजी तालाब के समीप सामाजिक सौहार्दता के प्रतिक हजरत चांदशाह वली, गुलाब शाह वली की दरगाह पर आज से उर्स का आयोजन किया जा रहा है। इस उर्स का आयोजन 22 मई तक जारी रहेगा। हर साल आयोजित होने वाला यह उर्स पिछले दो साल से कोरोना संक्रमण के चलते बड़े पैमाने पर न आयोजित होकर मुख्तसर अंदाज मनाया गया। चूंकि अब कोरोना गाइड लाइन के लगभग सारे प्रतिबंध हटा लिए गए है, तो इस वर्ष हजरत चांदशाह वली -गुलाबशाह वली का यह उर्स वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। झाबुआ शहर में होने वाले इस उर्स को दूर-दूर ख्याति प्राप्त है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पिछले दो सालों से जायरीन यहां चांदशाह वली-गुलाबशाह की ज्यारत को नहीं पहुंच सके। दो साल बाद होने जा रहे इस वृहद आयोजन में काफी संख्या में जायरीनों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। सामाजिक सौहार्दता का प्रतिक माने जाने वाले इस उर्स में दूर-दूर से सभी समाज के लोग आकर शामिल होते है। कई लोग मन्नत लेने तो कई लोग मन्नत पूरी होने पर हजरत चांदशाह वली- गुलाबशाह वली की चौखट पर अपना मत्था टेकने आते है।

इस वर्ष आज यानि 19 मई से उर्स का आगाज कुरआन ख्वानी और उसके बाद चादर शरीफ के जुलूस के साथ होने जा रहा है। कमेटी मेंमबरों के अनुसार आज सुबह 8 बजे कुरआन ख्वानी का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे चादर व संदल का जुलूस हुसैनी चौक कैलाश मार्ग से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ आस्ताने आलिया पर पहुंचेगा। यहां अकीदत के साथ चादर पेश की जाएगी। इसके साथ ही दरगाह पर परचम कुसाई (झंडा चढ़ाना) की जाएगी। रात 9.30 बजे से मिलाद शरीफ का आयोजन होगा।

20 मई शुक्रवार को रात 10 बजे से महफिले शिमा यानि कव्वाली का आयोजन होगा। दरगाह पर आयोजित होने वाली महफिल में उत्तरप्रदेश के बदायू के प्रसिद्ध कव्वाल ठाकुर अवेंद्रसिंह और पार्टी अपने कलाम पेश करेगी। इसके अलावा उत्तरप्रदेश के ही मुरादाबाद जिले के संभल के कव्वाल सरफराज चिश्ती अपने बेहतरीन कलाम पेश करेंगे।

21 मई शनिवार को महफिले शिमा में मेरठ के प्रसिद्ध कव्वाल आमिल आरिफ और दिल्ली से गुलाम फहीम वारसी अपनी कव्वालियां पेश करेंगे। 22 मई रविवार को उर्स का समापन होगा। इस दिन महफिले रंग का आयोजन किया जाएगा। यहां भी कव्वाल अपनी -अपनी कव्वालियों के साथ रंग की प्रस्तुति देंगे। इसके बाद फातेहा ख्वानी और लंगर का इंतेजाम भी उर्स कमेटी द्वारा किया गया है।

वेतन नही मिलने से 200 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताए परेशान

परिवार चलाने में मुश्किल, वेक्सिनेशन के लिए किये कार्य का भुगतान भी बाकी, जिले से जारी निर्देश के बाद भी परेशान आशा कार्यकर्ता

माही की गूंज , पेटलावद ।

स्वास्थ्य व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रो तक सुचारू रुप से संचालित करने के लिए मामूली वेतन पर आशा कार्यकर्ताओ की भर्ती की गई है, लेकिन विभाग द्वारा इनको दिये जाने वाला मामूली वेतन भी समय से नही दिया जा रहा। जिससे घर चलाने में परेशानीयो का सामान करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ता का मार्च माह से वेतन बाकी है जिसमे से उनका 30 से 40 प्रतिशत वेतन भुगतान किया, जबकि अप्रैल माह का वेतन अब तक नही डला है। आशा कार्यकर्ताओ का कहना है कि, हमको वेतन समय से नही मिल रहा जिससे परिवार के नियमित खर्चो के लिये परेशान होना पड़ रहा है। वही भोपाल स्तर पर कार्य कर रहे संगठन में समय पर वेतन और प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग की थी, जिसके बाद भोपाल से मिले पत्र के आधार पर जिले के सभी विकास खंण्ड के खंण्ड चिकित्सा अधिकारीयो को माह की 5 तारीख तक वेतन भुगतान करने के निर्देश जारी 2 मई को किये थे लेकिन आदेश के 18 दिन बीत जाने के बाद भी भुगतान नही हो पाया है।

बीएमओ एमएल चौपड़ा का कहना है कि, बजट कम होने के कारण वेतन कम दिया था। वर्तमान में बकाया वेतन के लिए समस्त प्रक्रिया कर दी है, एक-दो दिन में वेतन का भुगतान हो जाएगा।

कोविड-19 वेक्सिनेशन का भुगतान भी बाकी

विकास खण्ड में 200 से अधिक आशा कार्यकर्ता कार्यरत है। कई कार्यकर्ताओ का कोविड-19 के वेक्सिनेशन के दौरान दी गई, अतिरिक्त सेवाओं के लिए होने वाला भुगतान भी बकाया है। उनको 200 रुपये प्रतिदिन के अतिरिक्त कार्य दिवस के अनुसार भुगतान होना था। जो कि, जनवरी 2021 से बकाया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी पत्र में भी वेक्सिनेशन के कोविड-19 के लिए लंबित भुगतान करने के निर्देश है।

बीएमओ चोपड़ा का कहना है कि, शासन के निर्देशानुसार वेतन के साथ अतिरिक्त राशि लगभग 28 सौ से 3 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जिन कार्यकर्ताओ का भुगतान लंबित है उनको दिखवा लेते है।

विभागीय घोटाला होने की संभावना

इस मामले में विभाग में बड़ा घोटाला भी उजागर हो सकता है। कर्मचारी संगठन ने आशा कार्यकर्ताओ के बकाया भुगतान के लिए जिला कलेक्टर को दिपावली पूर्व ज्ञापन देकर भुगतान की मांग की थी, जिस पर कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को बकाया भुगतान करने के लिए निर्देशित किया था। मिली जानकारी के अनुसार जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने एक वेक्सिनेशन सेंटनर पर काम करने वाली पूरी टीम में 2 सौ रुपये बाट दिए, मतलब 4 लोगो की टीम एक सेंटर पर रही, तो सभी को 50-50 रुपये का भुगतान किया गया। जबकि आशा कार्यकर्ताओ का कहना है कि, उनको 2 सौ रूपये प्रतिदिन के अनुसार देने का कह कर वेक्सिनेशन में ड्यूटी लगाई थी, जिसका की भुगतान नही हुआ है। मामला जांच का विषय है कि, कोविड वेक्सिनेशन के दौरान ऑपरेटर, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओ को कितना भुगतान सरकार द्वारा किया और विभाग द्वारा कितना भुगतान किया गया।

21 जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमे वेतन और वेक्सिनेशन की बकाया राशि का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए गए है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति केंद्र निर्माण योजनांतर्गत मूंग वितरण

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

सारंगी उचित मूल्य दुकान पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मूंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें प्राथमिक शाला के प्रति छात्र, छात्रा को 10 किलो और माध्यमिक शाला के छात्र-छात्रा को 15 किलो मूंग वितरित किया गया। इस अवसर पर सारंगी सरपंच फुंदी बाई मैड़ा, उपसरपंच परमानंद पाटीदार ,मंडल मीडिया प्रभारी सुरेशचंद्र परिहार, नोडल अधिकारी राजेश गामड़, उचित मूल्य दुकान सेल्समैन सतीश पाटीदार, प्राथमिक व माध्यमिक शाला के शिक्षकगण उपस्थित रहे।

कैसे पूरा होगा डेढ़ लाख रुपये में प्रधानमंत्री आवास...?

माही की गूंज, थांदला।

भारत सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना को मकान बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 50 हजार की राशि अपर्याप्त है। बढ़ती महंगाई, परिवहन लागत अधिक होने से 10 बाय 20 का कमरा भी बनाना मुश्किल है ऐसे में शासन द्वारा ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने का सपना अधूरा साबित होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में शासन द्वारा 1 लाख 50 हजाार प्रधानमंत्री आवास हेतु दिए जाने का प्रावधान सुनिश्चित है, यदि हितग्राही के यहां शौचालय नहीं है तो 12 सौ रूपये पूर्व से शौचालय हेतु काटे जाएंगे। शासन द्वारा 18 हजार मनरेगा से मजदूरी के भी देय है। वहीं दूरस्थ अंचल में रहने वाला हितग्राही, सीमित राशि में आवास कैस बना पाएगा। आवास में प्रयुक्त होने वाली सामग्री सीमेंट, सरिया, गिट्टी रेट के साथ कारीगर व मजदूर की प्रतिदिन लागत अधिक होने से उसके लिए मकान बनाना महज स्वप्न ही साबित होगा। ऐसे में हितग्राही को मकान निर्माण में पानी भी क्रय करना है, महज 1 लाख 38 हजार में हितग्राही मकान बनाने की कल्पना को पूरी नहीं कर सकता है। भारत शासन ने यह महत्वपूर्ण

योजना 2015 से आरंभ की थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख़ 50 हजार रुपए व शहरी क्षेत्र में 2 लाख 50 हजार रुपए देने का प्रावधान है, शासन में बैठे जिम्मेदारों को भी इस बात का पता है कि, उक्त राशि से हितग्राहियों के मकान बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। बढ़ती महंगाई से नगरी क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास अधूरे रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त राशि के अभाव में कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े है। उक्त योजना से हितग्राही और अधिक कर्जदार बनता जा रहा है।

क्या बोले जिम्मेदार

इस संदर्भ में भाजपा प्रदेश मंत्री संगीता सोनी का कहना है कि, बढ़ती महंगाई से प्रधानमंत्री आवास पूर्ण नहीं होंगे वे शीघ्र ही प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में क्षेत्रीय सांसद के साथ मुख्यमंत्री से चर्चा कर राशि बढ़ाने की मांग उठाएगी। केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना के हितग्राही लाभान्वित हो, यही भाजपा सरकार का संकल्प है। किंतु यह राशि अपर्याप्त है इस समस्या का हल करने के लिए वह संगठन स्तर पर उठाने का प्रयास करेगी।

केन्द्रीय बैंक में अव्यवस्थाओं को लेकर किया प्रदर्शन

माही की गूंज, थांदला।

गर्मी में 40-45 डिग्री तापमान में भूखे, प्यासे गरीब आदिवासी किसान भाई घंटों तपती धूप में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ग़रीब आदिवासी किसान भाईयो के लिए बैंक में बैठने के लिए ना छायादार जगह है, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है। व्यापारीयो के लिए बैंकों में सुविधा उपलब्ध है। पर ग़रीब किसानों के लिए बैंकों में कोई भी सुविधा क्यो उपलब्धं नहीं है। यहां तक की बैंक के कर्मचारी, ग़रीब किसानो से सीधे मुंह बात तक नही करते है। सहकारी केन्द्रीय बैंक थांदला में अव्यवस्थाओं को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है पर शायद यहां ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जब यह जानकारी समाजसेवी कार्यकर्ताओ को मिली तो उन्होंने किसानों की सुविधाओं को लेकर बैंक के बहार प्रदर्शन किया।

जानकारी देते हुए प्रताप कटारा ने बताया कि, 40 से 45 डिग्री तापमान में हमारे गांवों से कई किसान भाई 50 से 60 कि.मी दुर से सुबह जल्दी निकलकर सहकारी बैंक शाखा थांदला किसान लोन की राशि निकालने के लिए आते हैं। और कडी धुप में लाईन में खडे होकर अपनी बारी का इंतजार करते है। उनके लिए न खडे रहने के लिए न टेंट की व्यवस्था है ना ही पिने के पानी की सुविधा, किसानों के लिए बैंकों में कोई सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं है।

समाजसेवी कार्यकर्ताओ ने बैंक प्रबंधक से निवेदन किया है कि, आप शाखा के बाहर छांव के लिए टेंट और पीने के पानी एवं कुर्सीयों की व्यवस्था करें, ताकि कोई व्यक्ति कडी धूप में बीमार ना हो जाएं। बैंक प्रबंधक ने सामाजिक कार्यकर्ता को आश्वासन दिया है कि, जल्दी ही आपकी मांगे पुरी कर दी जाएगी। प्रदर्शन में समाजसेवी कार्यकर्ता प्रताप कटारा, दिलीप डामोर, दुला भुरीया, शांतु बारिया, रमेश कटारा, रूपसिंह गरवाल, कल्पेश मुणिया, कपिल गणावा, बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु टीम ने किया भ्रमण, गंदे पानी को साफ कर किया जाएगा उपयोग

60 लाख की लागत से लगेगा प्रोजेक्ट, खराब हो चुकी नालियों का गंदा पानी पहुँचाना बड़ी चुनौती

माही की गूंज, पेटलावद।

जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रंबंधन कार्य के तहत जिले के ऐसे बड़े ग्राम जिनका अपशिष्ट जल काफी मात्रा में निकलता है, उसको विभिन्न तकनीकों से उपचारित कर पुनः उपयोग में लेने हेतु यूनिसेफ दिल्ली के सहयोग से प्राइमूव पुणे की तकनीकी टीम जिले के संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षित एवं हैण्डहोलिंडग स्पोर्ट देने का कार्य कर रही है। विगत दिनों उक्त तकनीकी दल द्वारा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बामनिया का भ्रमण कर, ग्राम के अपशिष्ट जल को डी-वाट्स तकनीकी द्वारा उपचारित करने के लिए तकनीकी प्रक्रिया ड्रॉइंग, डिजाइन एवं स्टीमेट आदि तैयार करने की प्रक्रिया बताई गई। टीम द्वारा पूरे गाँव का भ्रमण कर पुलिस चौकी के पीछे उलपब्ध जमीन को देखा एवं इसका डमी ले आउट उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण पेटलावद में दिया गया। इस अवसर पर प्राइमूव पुणे की ओर से रमेश अग्रवाल एवं आकाश गायकवाड़ ने तकनीकी मार्गदर्शन दिया।

इस कार्यक्रम में पेटलावद एसडीएम शिशिर गेमावत, जनपद पंचायत सीईओ अमित व्यास उपस्थित रहे, साथ ही सहायक यंत्री सी.एस.अलावा, ब्लाक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन पेटलावद बाबुलाल परमार, उपयंत्री राकेश पटेलिया, जी.एस. अहिरवार, पवन गुप्ता, नीरज पांचाल, लोकेश सोलंकी, नरेंद्र चौहान एवं थांदला जनपद पंचायत से सहायक यंत्री, ब्लॉक समन्वयक सुश्री ज्योति भाभर एवं समस्त उपयंत्री तथा ग्राम पंचायत बामनिया सरपंच श्रीमति रामकन्या मकोड़, रोजगार सहायक भारत अरड़ उपस्थित रहे।

उत्कृष्ट मैदान में प्रोजेक्ट के डेमो का तकनिकी जानकारी लेते हुए विकास खण्ड के अधिकारी और उपयंत्री।

चोक और अव्यवस्थित ड्रेनेज लाइन के कारण गंदा पानी प्रोजेक्ट तक पहुँचना मुश्किल

विकास खण्ड की ज्यादातर बडी पंचायतो में ड्रेनेज लाइन (नाली निर्माण) अव्यवस्थित है, जिस कारण नाली का पानी प्रोजेक्ट तक सही मात्रा में पहुँचना काफी मुश्किल है। ग्राम पंचायत बामनिया में लगभग 55 से 60 लाख की लागत से प्रोजेक्ट लगाए जाने का विचार किया जा रहा है और इसके लिए उपयुक्त भूमि भी देख ली गई है। यदि प्रशासन का ये प्रयास सफल होता है, तो पानी साफ हो कर पेटलावद रोड स्थित पाटड़ी नदी में डाला जा सकता है। जिससे नदी के आस-पास की खेती को नया जीवन मिलने के साथ-साथ वाटर लेवल भी बढ़ाने का काम हो सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के संचालन की सबसे बड़ी चुनौती नगर की अव्यवस्थित नाली निर्माण है, जिसका पानी इस प्रोजेक्ट तक पर्याप्त मात्रा में नही पहुँच पायेगा। नगर की ज्यादातर नालियां खुली पड़ी है और बड़ी नालियों से जुड़ी हुई नही है, जिस कारण नालियों में कचरा भरा रहता है और ज्यादातर पानी सड़को पर फैल जाता है या फिर एक ही स्थान पर सड़ता है।

ग्राम पंचायत सरपंच रामकन्या मखोड ने इस सम्बंध में बताया कि, नालियों की समस्या तो है जिसके लिए फंड की मांग की ताकि नालियों को सुव्यवस्थित कर घरों से निकलने वाला गंदा पानी बड़ी मात्रा में इस प्रोजेक्ट तक पहुँचाया जा सके।

अच्छी पहल

भाजपा के जिला कार्यकरणी सदस्य ब्रजभूषण सिंह परिहार, पूर्व उपसरपंच अजय जैन, भाजपा के अजज़ा मोर्चा के मण्डल अध्यक्ष सोहन डामर आदि ने इस प्रोजेक्ट को अच्छा बताते हुए कहा है कि, जिस प्रकार से पानी का अपव्यय हो रहा है, पानी को सुरक्षित करने का समय आ गया है और प्रशासन का इस दिशा में ये सराहनीय प्रयास है। इस प्रोजेक्ट के संचालन के लिए शासन को इसमें आने वाली परेशानियों को भी दूर करना चाहिए। अजय जैन ने कहा है कि, आनी वाली पीढ़ी के लिए जल संरक्षित करना इस पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होगा, ऐसे में ऐसी योजनाओं को सफल बनाने के लिए कार्य करना जरूरी है।

अतिक्रमण और भ्रष्टाचार: गर्मी में पशुओं के पीने के पानी के स्त्रोत (होद) तक को नहीं छोड़ा

माही की गूंज, झकनावदा।

पेटलावद तहसील के अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी पंचायत (उप तहसील) झकनावदा की जहां पर ठीक ग्राम पंचायत के सामने एवं गणेश मंदिर के पीछे जहां पर कभी गर्मी में पशु अपनी प्यास बुझाते थे, जहां कभी पशुओं के लिए एक होद हुआ करता था। वहां पर तत्कालीन सचिव भीम सिंह कटारा की मिली भगत एवं अतिक्रमणकारियों की दबंगता से वहां पर पहले सुनियोजित तरीके से होद के ऊपर मिट्टी डाली गई एवं होद को पूरी तरह से भर दिया गया। पंचायत द्वारा वहां पर अतिक्रमण करवाया गया। अब वहां पर चद्दर की घुमटिया पड़ी हुई दिखाई देगी, इससे साफ प्रतीत होता है कि, पंचायत अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है क्योंकि यह गुमटियां कभी पंचायत के ठीक सामने पड़ी थी, जहां पर अब नवीन अटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गये है। जीवदया समिति के सदस्यों ने शासन से मांग की है कि, वहां से तत्काल अवेध गुमटियां हटाए एवं पंचायत को आदेश दें कि वहां पर गर्मियों में पशुओं के पिने के पानी के लिए एक नवीन होद बनवाएं एवं उसमें टैंकर या अन्य स्त्रोत से सुचारू रूप से पानी भरवाए और जो भी राशि उसमें लगे उसकी भरपाई पंचायत उठाए।

ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष जगपाल सिंह राठौर का कहना है कि, जो वर्तमान में 7 नवीन अटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गये। उसमें भी अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए आपस में बंदरबांट की गई है। अपात्र लोगों को ही आवंटित किया गया है। जबकि शासन की जो भी गाईडलाइन है, उसके अनुसार सार्वजनिक नीलामी होना चाहिए। रही बात पशुओं के पीने के लिए पानी के हौद की तो वहां पर शासन को तत्काल प्रभाव से पंचायत को आदेशित करना चाहिए कि, जो लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसे हटाए एवं वहां पर पशुओं के पीने के पानी के लिए फिर से एक होद बनवाएं एवं उसे प्रतिदिन पानी से भरें।

महाकाल मित्र मंडल सदस्य के सदस्य का कहना है कि, पंचायत के सामने जो अवैध घुमटिया रखकर जो अतिक्रमण पंचायत द्वारा करवाया गया है। वहां पर कभी पशुओं के पिने के पानी का होद हुआ करता था। वहां पर अब अवैध अतिक्रमण कर लिया गया। अब नगर में पशुओं के पिने के पानी लिए कोई व्यवस्था नहीं है यह एकमात्र गणेश मंदिर के पीछे स्थित होद ही एकमात्र स्त्रोत था। प्यासे पशु दिन भर इधर-उधर घूमते हुए दिखाई देंते और नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर है। शासन द्वारा समय-समय पर पशुओं के लिए पीने के लिए पानी के होद मंजूर किए जाते है, परंतु यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि, यहां पर पशुओं के लिए होद मंजूर हुए थे, वह भी पंचायत द्वारा फर्जी तरीके से बिल लगाकर उसकी राशि का आहरण कर लिया गया।

पं.उत्तम स्वामी जी के मुखारविंद से होगी भागवत कथा

माही की गूंज, झकनावदा।

पेटलावद विकास खण्ड में एक के बाद एक बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे है। पेटलावद में सम्पन्न आई माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य सफल आयोजन के बाद ग्राम झकनावदा में जन-जन की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र भगवान महादेव शिव परिवार, हनुमान जी, श्री नवग्रह, श्री भैरवनाथ, यति महाराज प्रतिष्ठा एवं पंचकुंडत्मक महारुद्र एवं शतचंडी महायज्ञ भागवत ज्ञान गंगा महासंगम महोत्सव का आयोजन 21 मई से 27 मई तक किया जा रहा है।

जिसमें 1008 श्री महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज, 1008 रामेश्वर गिरी जी महाराज सिंघेश्वर धाम, 1008 योगेश जी महाराज बालीपुर धाम, 1008 दयाराम जी महाराज पीपलखुटा अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। इस महोत्सव में प्रतिदिन रात्रि में धार्मिक सांस्कृतिक एवं भक्ति संगीत का कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। समिति के मुख्य संरक्षक भूपेंद्र सिंह राठौर, अध्यक्ष गोपाल राठौड़, मुख्य परामर्शदाता राम जोशी, संयोजक प्रदीप पालरेचा, सचिव हरिराम पडियार और राजेंद्र मिस्त्री ने क्षेत्र की समस्त जनता से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेंने का अनुरोध किया है।

सड़क के मेंटेनेंस के लिए थांदला-बदनावर राज मार्ग पर फिर से चुकाना पड़ेगा टोल

माही की गूंज, पेटलावद।

यदि आप थांदला-बदनावर मार्ग से गुजर रहे है तो अब आपको फिर से टोल से चुकाना पड़ेगा। फरवरी माह में बन्द हो चुका टोल गेट एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लगातार स्टेट हाइवे की बिगड़ती हालत को सुधारने और उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार ने स्टेट हाइवे पर फिर से टोल के टेंडर कर दिए, जिसके बाद केटी कम्पनी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर टोल लिया है, मिली जानकारी के अनुसार कम्पनी 08 करोड़ सालाना से अधिक राशि सरकार को दो वर्ष तक देगी। पेटलावद से 8 किलोमीटर दूर लगा टोल गेट लगभग 7 दिन पूर्व से शुरू हो चुका है।

फरवरी में ही मिली थी राहत, रोड मेंटेनेंस के लिये फिर शुरू हुआ टोल

पिछली टोल कम्पनी का टेंडर फरवरी में खत्म होने के बाद मार्ग से गुजरने वाले लोडिंग वाहनों को टोल से राहत मिली थी। मार्ग से रास्ता बदल कर चलने वाले वाहन सीधे इस मार्ग से गुजर रहे थे, टोल बन्द होने से वाहनों का अतिरिक्त दबाव पड़ा। जिसके चलते स्टेट हाइवे की हालत खराब हो गई थी, जिसको सुधारने के लिए फिर से टोल शुरू किया गया।

कमर्शियल लोडिंग वाहनों को चुकाना होगा टोल

स्टेट हाइवे पर लगने वाला टोल पहले की तरह केवल कमर्शियल और लोडिंग वाहनों पर लगेगा। हल्के लोडिंग वाहनों को 115, ट्रक को 290 और बड़े भारी वाहनों को इस मार्ग से गुजरने के लिए 575 रुपये चुकाने होगे। टोल गेट शुरू होने से पहले टोल कम्पनी द्वारा रोड का किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नही किया है, कई स्थानों पर गड्ढे होने के कारण वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

फिर से रास्ता बदलेंगे बड़े वाहन

टोल शुरू होने के बाद मार्ग से गुजरने वाले बड़े वाहन जो कि, टोल बन्द होने के बाद इस मार्ग से बेफिक्र हो कर गुजर रहे थे, एक बार फिर टोल बचाने के लिए अपना रास्ता बदलेंगे। स्टेट हाइवे से गुजरने वाले वाहन सारंगी फंटे, बरवेट, रायपुरिया वाला मार्ग और पेटलावद नगर से बीच से होकर रायपुरिया होकर निकलेगे। जिससे इन मार्गो पर अतिरिक्त वाहनों दबाव का पड़ेगा। पूर्व की टोल कंपनी के कर्मचारियों इन वाहनों को स्टेट हाइवे निकालने के लिए विवाद की स्थिति निर्मित करते थे जो स्थिति पुनः निर्मित हो सकती है।

ये देनी होगी सुविधा

टोल कंपनी को स्टेट हाइवे का न केवल मेंटेनेंस करना है, बल्कि मार्ग से गुजरने वाले वाहनों के लिए अन्य सुविधा 24 घंटे की एम्बुलेंस, दुर्घटना की स्थिति में मार्ग को जल्द से जल्द शुरू करना, मार्ग पर लगने वाले बोर्ड, किलोमीटर को दुरुस्त रखने जैसी सुविधाये भी टोल कम्पनी को देनी होगी।

संपादकीय

कांग्रेस का चिंतन शिविर

भले की उदयपुर में संपन्न कांग्रेस के तीन दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी ने नीतियों की उन खामियों को स्वीकार किया है, जिसके चलते पार्टी का पराभव हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जनता का विश्वास हासिल करने को गंभीर जमीनी पहल करने की जरूरत है। पार्टी ने सम्मेलन में स्वीकार किया कि, जनता से जुड़ाव टूटा है और इसके लिए पार्टी को सीधे जनता से संवाद की स्थिति बनानी होगी। साथ ही नीतियों से जनमानस से सार्थक संवाद की जरूरत पर भी बल दिया गया। लेकिन एक हकीकत यह भी कि लोगों से सीधे जुड़ने के लिए यात्राओं से ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती है। जिसके लिए बड़े बदलाव जरूरी हैं। जिसके लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से बेहतर तालमेल भी हो, जिन्हें यह कहकर कांग्रेस खारिज नहीं कर सकती कि उनकी कोई निर्णायक विचारधारा नहीं है। पार्टी को जीवंत बनाने के लिए 'एक परिवार, एक टिकट' के विचार पर अपवादों के साथ सहमति बनाना अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकता। हालांकि, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने 'रोजगार दो' और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 'भारत जोड़ो' यात्रा निकालने की बात कही है, लेकिन दरकते जनाधार को हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक प्रयासों की जरूरत होती है।

दरअसल, अप्रभावी संचार व संवाद की कमजोर प्रणाली ही कांग्रेस की लोकप्रियता में गिरावट की अकेली वजह नहीं है। ऐसे तमाम कारण हैं जिनके चलते कांग्रेस की यह स्थिति हुई है। जिसमें निर्णय लेने में देरी, प्रत्याशियों के चयन में पारदर्शिता का अभाव, अंतिम समय में टिकट वितरण में अराजकता, आक्रामक व तार्किक विरोध का अभाव, केंद्र सरकार के संदिग्ध निर्णयों के खिलाफ जनमत न तैयार कर पाना जैसे कारण भी शामिल रहे हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ विपक्ष को एकजुट न कर पाना तथा आसमान छूती महंगाई के मुद्दे को जन-जन तक न पहुंचा पाना भी कांग्रेसी की विफलता को दर्शाता है। दरअसल, आम जनता से जुड़े और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के खिलाफ एकजुटता के साथ आवाज बुलंद करने की जरूरत होती है।

नि:संदेह, कांग्रेस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि, पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे युवाओं का पार्टी की रीति-नीतियों से मोहभंग क्यों होता रहा है। इस बाबत योजना बनाकर पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए कि, युवाओं पर महत्वाकांक्षी व वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध न होने के आरोप लगाने के बजाए उनकी ऊर्जा का उपयोग पार्टी के विस्तार के लिए कैसे करना है। इस दिशा में पचास से कम आयु वर्ग के नेताओं के लिए पार्टी में आधे पद आरक्षित करना सार्थक कदम हो सकता है, हालांकि इस फैसले की व्यावहारिकता का अभी मूल्यांकन बाकी है। नि:संदेह, भाजपा ने लंबे समय तक केंद्रीय सत्ता में रही कांग्रेस के खिलाफ जनमत तैयार करने में बेहतर पार्टी संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं का उपयोग किया। इस दिशा में चुनाव प्रबंधन समिति का गठन करने का कांग्रेस का निर्णय स्वागत योग्य है। मगर सिर्फ प्रधानमंत्री की आलोचना करने मात्र से पार्टी को बेहतर परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सवाल यह है कि, चिंतन शिविर में जिन कदमों को उठाने की घोषणा हुई है क्या उनके जरिए पार्टी खुद को नए वक्त की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल पाएगी...? बहरहाल, पार्टी को इस बात का अहसास अच्छे ढंग से हो चुका है कि पार्टी को मौजूदा चुनौतियों से उबारने का कोई छोटा रास्ता बाकी नहीं है। उसे बड़े पैमाने पर कदम उठाकर पार्टी की ?वापसी सुनिश्चित करनी होगी। देखना होगा कि, चिंतन शिविर में घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन कितने फुलप्रूफ तरीके से होता है। साथ ही किस हद तक देश की आर्थिक सुधार की नीतियों के पुनर्निर्धारण की मुहिम को विमर्श का मुद्दा बना पाती है। हालांकि, महिला आरक्षण व कुछ अन्य मुद्दों पर पार्टी की नीति लोकलुभावन शैली के ही अनुरूप है। साथ ही यह संदेश जाना जरूरी है कि, पार्टी असमंजस व बचाव की मुद्रा से निकलकर आक्रामक तेवरों के साथ मैदान में आई है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व में दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत दिखना भी जरूरी है। देखना होगा कि, जिन मुद्दों पर देश के राजनीतिक मिजाज में परिवर्तन आया है कांग्रेस उसको लेकर क्या रणनीति अपनाती है।

कश्मीरी पंडित विवादः चुनाव के इरादे ध्वस्त...?

ओमप्रकाश मेहता

पूरा देश आज विभिन्न विवादों को लेकर उद्वेलित है और सरकार पर काबिज दिग्गज मौन साधे हुए है। आज एक ओर जहां कश्मीरी पण्डितों व गैर कश्मीरियों की लगातार हत्याओं से जम्मू-कश्मीर अशांत है। वही विभिन्न मसलों को लेकर देश में फैल रहे साम्प्रदायिक उन्माद से देश का आम नागरिक डरा-सहमा है और जिसे सामने आकर इन विध्वंसक गतिविधियों को रोकना चाहिए। वे सरकार में काबिज लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे है, उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर ऐसी परिस्थितियों में वे कब्जा कैसे कर पाएगें? उन्हें सिर्फ सियासत से मतलब है, आम देशवासी को दुःख-दर्द या देश की परेशानी से कोई सरोकार नहीं, इस स्थिति को लेकर सिर्फ देश चिंतित है, इसे चलाने वाले नहीं?

हमारी धरती के स्वर्ग जम्मू-कश्मीर की स्थिति आज यह है कि केन्द्र के अधीन और उप-राज्यपाल की सरपरस्ती में पल रहे इस राज्य में स्थिति दिनों-दिन भयावह होती जा रही है। एक ओर जहां खौफजदा कश्मीरी पण्ड़ितों को अपनी सुरक्षा को लेकर पहली बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और सरकारी नौकरी से सामुहिक इस्तीफा देना पड़ रहा है, वहीं इस राज्य का आम नागरिक भी अपनी दैनंदिनी परेशानियों से जूझ रहा है। पूरे देश में पर्यटन उद्योग से सर्वाधिक आय वाला राज्य आज एक-एक पैसे को तरस रहा है। आम कश्मीरी के भी सभी आय के साधन पिछ्ले दो साल से खत्म हो गए है। एक ओर कश्मीर के ये हाल है, दूसरी और केन्द्र सत्ता स्थापित करने के सपनों में खोई है।

इसी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 खत्म कर इस राज्य का विशेष दर्जा खत्म किया था और यहां के नागरिकों को रंगीन सपने दिखाने का प्रयास किया था, वे सपने आज बदरंग होकर कश्मीरियों के सामने आ रहे हैं। पिछ्ले तीन दशक से अपनी जन्मभूमि से निष्कासित कश्मीरी पण्डितों को केन्द्र में सत्तारूढ़ इसी राजनीतिक दल ने अपने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में उनकी खुशहाली के सतरंगी सपने दिखाये थे, किंतु इस दल के केन्द्र में सत्तारूढ़ होने के आठ साल बाद भी कश्मीरी पण्डित अपनी जन्मभूमि पर बसने के लिए तरस रहे है। यहां तक तो ठीक है अब तो उनकी हत्याएं तक की जाने लगी है, पिछ्ले दो दिन में दो हत्याएं इसका ज्वलंत व ताजा उदाहरण है और जब ये कश्मीरी पण्डित अपनी जीवन रक्षा की मांग उठाने के लिए एकत्र होते है तो पुलिस उन पर लाठियां भांजती है।

अब इन कश्मीरी पण्डितों का सरकार से एक ही सवाल है कि ''आखिर वे कहां जाए?'' अब अपनी नौकरियों से सामुहिक इस्तीफें दे देने के बाद इन कश्मीरी पण्डितों के सामने अपने जीवन यापन का भी सवाल खड़ा हो गया है। चूंकि दो दिन पहले एक कश्मीरी पण्डित युवक राहुल भट्ट की उसके कार्यालय में उसका नाम पूछकर हत्या की गई थी। इसलिए डरे-सहमें कश्मीरी पण्डितों ने अपनी नौकरियों से सामुहिक इस्तीफें दे दिए और पहली बार ऐसा व्यापक प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें कई कश्मीरी पण्डित घायल हुए।

अब स्थिति यह है कि, एक ओर जहां केन्द्र में सत्तारूढ़ दल जम्मू कश्मीर विधानसभा के यथाशीघ्र चुनाव करवा कर अपनी सत्ता कायम करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर आम कश्मीरी केन्द्र सरकार व सत्ताधारी दल से काफी नाराज है। अभी तक अनुच्छेद 370 खत्म करने की पीड़ा से वह उभर नही पाया है वहीं कश्मीर में आर्थिक संकट व जीवन यापन की परेशानी से वह व्यथित है। जहां तक इस राज्य की राजनीतिक स्थिति का सवाल है। अब धीरे-धीरे वहां के स्थानीय राजनीतिक दल आपसी मतभेदों के बावजूद केन्द्र सरकार व भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे है। अब केन्द्र के सामने जहां इस राज्य में चुनाव कराने की संवैधानिक मजबूरी है, वहीं यहां राजनीतिक स्थिति भाजपा के अनुकूल बन नहीं पा रही है, इसी अहम दुविधा में मोदी सरकार है।

यह तो हुई एक राज्य विशेष की बात। अब यदि हम देश के मौजूदा माहौल पर गौर करें, तो उसे देखकर भी हर किसी को भारी चिंता होती है। देश का साम्प्रदायिक माहौल दिनों दिन विभिन्न मसलों को लेकर विस्फोटक होता जा रहा है। फिर वह चाहे मंदिर-मस्जिद का मामला हो या अन्य सामाजिक व आस्था से जुड़े मसलों का। इसीलिए आज देश का हर जागरूक नागरिक चिंतित है और सरकार मौन। अब ऐसी स्थिति के लिए क्या कहा जाए, किसे दोष दिया जाए व किसे दण्डित करने के बारे में सोचा जाए?

जो मंदिर में है, वही मस्जिद में भी है

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अदालतें क्या फैसला करेंगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन इतना समझ लीजिए कि यह मामला अयोध्या की बाबरी मस्जिद-जैसा नहीं है। कोई भी वकील या याचिकाकर्ता या हिंदू संगठन यह मांग नहीं कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को ढहा दिया जाए और उसकी जगह जो मंदिर पहले था, उसे फिर से खड़ा कर दिया जाए। इस तरह की मांगों पर 1991 से ही प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि संसद में यह कानून पास हो चुका है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थान जैसा था, वह अब वैसा ही रहेगा। इसीलिए यह डर पैदा करना कि ज्ञानवापी की मस्जिद को ढहाने की साजिश शुरु हो गई है, गलत है। यहां कुछ महिलाओं ने स्थानीय अदालत में जो याचिका लगाई हैं, उसका मंतव्य बहुत सीमित है। उनकी प्रार्थना है कि उन्हें मस्जिद के बाहरी हिस्से में बने गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा और परिक्रमा का अधिकार दिया जाए। कई वर्षों से मस्जिद की प्रबंध समिति ने इस पुरानी सुविधा को कुछ वर्षों से रोक दिया था। स्थानीय अदालत ने इस मस्जिद परिसर की जांच करने के आदेश दे दिए। जांच के परिणाम जगजाहिर हो गए। उनके कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। कुछ हिंदू प्रवक्ता कह रहे हैं कि मस्जिद में तो मंदिर के अवशेष भरे पड़े है। मुगल आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। इस पर मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को गिराने की साजिश शुरु हो गई है। सच्चाई तो यह है कि सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिर ही नहीं, देश के सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर विदेशी हमलावरों ने वहां मस्जिदें खड़ी की थीं। यह उन्होंने भारत में ही नहीं किया, स्पेन, तुर्की, इंडोनेशिया आदि कई देशों में किया है। सत्ता के भूखे इन ज़ालिम और जाहिल बादशाहों ने पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों को ताक पर रखते हुए दुनिया के कई मंदिरों और गिरजों को गिराकर अपने अहंकार को तुष्ट किया। उन्हें सर्वव्यापी अल्लाह से नहीं, अपनी सत्ता से सरोकार था। मैंने ईरान में वे मस्जिदें भी देखी हैं, जो पड़ौसी मुस्लिम शासकों ने गिराई हैं। दक्षिण भारत की एक जामा मस्जिद भी आगरा के एक मुस्लिम बादशाह ने गिराई थी, क्योंकि बादशाहत का रौब कायम करने के तीन बड़े साधन थे। पराजितों की औरतों पर कब्जा, संपत्ति की लूट-खसोट और उनके पूजा-स्थलों को भ्रष्ट करना। यदि इन कारणों से कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजा बनता है तो क्या उस पर कोई गर्व कर सकता है? किसी भी धर्म को माननेवाला सच्चा भक्त ऐसे पूजा-स्थलों को सम्मान की नजर से नहीं देख सकता। लेकिन उन्हें अब ढहाने के बात करना भी बर्र के छत्ते में हाथ डालने-जैसी बात है। जो जैसा है, उसे वैसा ही पड़ा रहने दें। वे शासकीय अत्याचारों के स्मारक बनकर खड़े रहेंगे लेकिन जो सच्चे ईश्वर या अल्लाहप्रेमी हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि वे मस्जिद में जाएं या मंदिर में जाएं? या दोनों में एक साथ चले जाएं। मंदिर में जो ईश्वर है, मस्जिद में वही अल्लाह है।

मानवीय मूल्यों व आदर्शों का भारत बनाएं

विश्वनाथ सचदेव

अध्यात्म के क्षेत्र में चिंतन-मनन का कुछ भी अर्थ होता हो, राजनीति की दुनिया में चिंतन का रिश्ता राजनीतिक नफा-नुकसान के गणित से ही जोड़ा जाता है। फिर भी राजनीतिक दलों के चिंतन-शिविर कभी-कभी धुंध साफ करने का काम कर जाते हैं। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस पार्टी के चिंतन-शिविर में इस दिशा में की गयी कोशिश का दिखना एक अच्छा संकेत है। कहते हैं, किसी भी मर्ज़ के इलाज से पहले उसका सही निदान ज़रूरी होता है। इस दृष्टि से देखें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस शिविर में सही नब्ज़ पर हाथ रखा है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि कांग्रेस का देश की जनता से संपर्क टूट गया है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह स्थिति चिंतन की आवश्यकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही यह चिंता का भी विषय होनी चाहिए।

देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। आज़ादी प्राप्त करने के बाद दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने देश का नेतृत्व किया है, देश को दिशा दी है। भारतीय जनता पार्टी समेत देश के अन्य कांग्रेस-विरोधी दल भले ही कुछ भी कहते रहें, यह एक हकीकत है कि प्रगति के जिस सोपान पर आज हमारा देश पहुंचा है, उसे वहां तक पहुंचाने में कांग्रेस की सरकारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश को कांग्रेस-मुक्त बनाने के अभियान में लगी भाजपा का नेतृत्व आज कांग्रेस के इस योगदान को भले ही नकार रहा हो, पर इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न केवल विकास की राह दिखाई थी, बल्कि उंगली पकड़ कर उस राह पर चलना भी सिखाया था। इस संदर्भ में जब हम अपने आसपास के देशों को देखते हैं तो आज़ादी के बाद के हमारे नेतृत्व की महत्ता का अहसास अनायास ही हो जाता है।

ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन-काल में सब कुछ ठीक-ठाक ही हुआ था। जवाहरलाल नेहरू से लेकर बाद के कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की रीति-नीति पर कई बार सवाल उठे हैं और सवालों का उठना ग़लत भी नहीं था। पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटकर इंदिरा गांधी ने जिस राजनीतिक कौशल का परिचय दिया था, वह अपने आप में एक मिसाल है। देश का भरपूर समर्थन और प्यार मिला था तब उन्हें। तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तब उन्हें दुर्गा कह कर देश की जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी थी। उसी जनता ने इंदिरा गांधी द्वारा की गयी आपातकाल की घोषणा को सिरे से खारिज कर दिया था। यह भूल एक अपराध की तरह कांग्रेस पार्टी के दामन का दाग़ बनी हुई है, लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा अपनी भूल स्वीकारने के बाद देश की जनता ने फिर से बागडोर उनके हाथों में सौंपी थी। जनता का यह विश्वास ही किसी भी नेतृत्व को, उसकी पार्टी को, औचित्य देता है।

लेकिन कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि उससे ग़लती नहीं होती। ऐसी ग़लतियां ही किसी पार्टी को जनता से दूर सकती हैं, जनता से उसके संपर्क कमज़ोर बनाती हैं। कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ। छह दशक के लंबे शासन में कई अवसर आये जब कांग्रेस की रीति-नीति से देश की जनता को शिकायत हुई। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। उसने ऐसे हर अवसर पर कांग्रेस नेतृत्व को पाठ पढ़ाया। यह पाठ पढ़ाने की इसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि पिछले दो आम चुनावों में कांग्रेस को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा।

लेकिन ऐसी पराजय में ही भविष्य की कोई जीत छिपी होती है। जनतंत्र में जीत-हार राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ज़रूरी है, न जीतने वाला अपनी जीत पर रीझे और न हारने वाला हार से निराश होकर बैठ जाये। ऐसे में दोनों को चिंतन की आवश्यकता होती है- जीतने वाले को अपनी जीत को मज़बूत बनाने के लिए और हारने वाले को हार की निराशा से उबरने के लिए। इसी चिंतन की अगली कड़ी है संकल्प-आने वाले कल को बेहतर बनाने का संकल्प। भारत जोड़ो का नारा देकर, और इसके लिए संकल्प-बद्ध होकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उदयपुर शिविर में यही कदम उठाने की घोषणा की है। पर सिर्फ घोषाणाएं पर्याप्त नहीं होतीं। घोषणाओं की क्रियान्विति उन्हें सही अर्थ देती है। भारत-जोड़ो अभियान ऐसी ही एक सार्थक कोशिश सिद्ध हो सकती है, बशर्ते कोशिश ईमानदार हो। पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ की जाये यह कोशिश।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस और देश की जनता के बीच दूरी बढ़ी है। टूटा है संपर्क। चुनावों के परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि इस दूरी को कम करने की कोशिशों में कहीं न कहीं कमी रही है। आवश्यकता इस कमी को दूर करने की है। बावजूद इसके कि आज कांग्रेस एक कमज़ोर स्थिति में है, हकीकत यह है कि कांग्रेस ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो भाजपा जैसी चुनौती का मुकाबला कर सकती है। यह सही है कि देश के अलग-अलग राज्यों में आज क्षेत्रीय दलों की स्थिति मज़बूत है। लेकिन इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा या कांग्रेस का विकल्प नहीं हो सकते। यहीं इस बात को भी समझना होगा कि आज राजनीति जो चुनौती देश के सामने प्रस्तुत कर रही है, वह राष्ट्रव्यापी है। यह चुनौती देश की एकता को बनाये रखने की है, धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने की कोशिशों को नाकाम बनाने की है। विविधता में एकता की बात तो सब करते हैं, पर इस भावना को मज़बूत बनाने के लिए एक भारतीय समाज की परिकल्पना को साकार करने की ज़रूरत है। भाषा, धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण से ऊपर उठकर चुनौती एक ऐसे भारत को बनाने की है जहां हर नागरिक पहले भारतीय होगा, फिर कुछ और।

आज देश जिस स्थिति में है उसमें राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। लड़ाई सत्ता की नहीं, विचार की है। हमारा भारत मानवीय आदर्शों और मूल्यों को मानने वाला हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम एक ऐसा समाज बनायें जिसमें हर नागरिक स्वयं को एक भारतीय के रूप में देखे। हर भारतीय एक जैसा हो। उसके अधिकार भी समान हों, और कर्तव्य भी। न तो किसी धर्म-विशेष का होने से कोई अधिक भारतीय बन सकता है और न ही किसी जाति-विशेष के आधार पर किसी के अधिकार दूसरे से अधिक हो सकते हैं। यह भारतीयता हमारे चिंतन का केंद्र होनी चाहिए। इस भारतीयता की भावना को मज़बूत बनाने की कोशिश हमारी चिंता का विषय होनी चाहिए। यह एक चुनौती है जो आज के भारत के सामने खड़ी है। हर राजनीतिक दल को, हर विचारधारा वाले भारतीय को यह संकल्प लेना होगा कि वह एक मज़बूत भारत बनाने की ईमानदार कोशिश करेगा। वह मज़बूत भारत हिंदू या मुसलमान का नहीं, सिख या ईसाई का नहीं, हर भारतीय का होगा। 'भारत जोड़ो' का यही मतलब हो सकता है।

20 लाख ईवीएम मशीने गायब? सरकार और चुनाव आयोग की चुप्पी?

सनत कुमार जैन

भारत में चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली तथा लाखों ईवीएम मशीने गायब होने, चुनाव के दौरान अनाधिकृत रुप से ईवीएम के परिवहन का मुद्धा गर्माता जा रहा है। ईवीएम से चुनाव गड़बड़ी होने के आरोप विगत कई वर्षों से विपक्षी दल लगाते रहे है। पिछ्ले कुछ चुनावों में ईवीएम मशीनों के अवैध परिवहन की घटनाओं, मतदान के अवैध मतपत्रों की गिनती तथा लाखों ईवीएम मशीन गायब होने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है।

ईवीएम की गायब होना और अकल्पनीय चुनावी जीतों में क्या कोई सम्बन्ध है। यह प्रश्न लगातारपूछा जारहा है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट में ईवीएम गायब होने का मुद्दा उठा था। कांग्रेस विधायक ने आरटीआई के हवाले से सदन में कहा था, कि 2016 से 2018 तक देश में 19 लाख ईवीएम गायब हैं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी यह मुद्दा उठाया। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक एचके पाटिल ने आरटीआई का हवाला देते हुए विधानसभा में जानकारी दी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई 9.6 लाख ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई 9.3 लाख ईवीएम 2016 से 2018 के बीच सरकारी रिकार्ड में गायब हो गईं। लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग चुप है।

कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने इस मामले में चुनाव आयोग का पक्ष जानने की कार्यवाही की है।

पाटिल ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की थी। उन्होंने 2750 पृष्ठ का जानकारी जिसे आरटीआई के माध्यम से ईवीएम बनाने वाली कंपनियां एवं चुनाव आयोग से किए गए, सवाल जवाब का ब्यौरा भी शामिल है। दस्तावेज के अनुसार ईवीएम बनाने वाली कंपनियों ने जो मशीनें चुनाव आयोग को सौंपी थी। उनमें से करीब 19 लाख मशीनों का कुछ अता-पता नहीं है। पाटिल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। 9 लाख 64 हजार 270 मशीनें वापस ही नहीं मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने यह भी दावा किया है कि उसने 2014 -15 के दौरान 62 हजार 183 मशीन सप्लाई की थी उनका भी कोई अता पता नहीं है. एसके पाटिल ने यह मुद्दा मार्च 2022 में विधानसभा में उठाया था। पाटिल ने कहा कि ईवीएम के परिवहन और खराब ईवीएम को डिस्पोज करने की प्रक्रिया में भी बहुत सी खामियां हैं। ईवीएम मशीनें बनाने वाली कंपनियों ने साफ कहा है कि ईवीएम मशीनों की उम्र 15 साल है। इसके बाद इनका उपयोग न किया जाए। किन्तु चुनाव आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर अमल नहीं किया और दूसरी तरफ अचानक जुलाई 2018 में नियम बना दिए गए।

2021 में प्रकाशित आयोग के मैन्युअल में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है, कि 15 वर्ष से पुरानी ईवीएम को किस प्रकिया के तहत नष्ट किया जा रहा है। इस की जगह मैन्युअल में खोया-पाया नाम से एक चैप्टर जोड़ा गया है जिससे साफ़ जाहिर होता है, कि लाखों ईवीएम मशीनें गायब हुईं। तीन साल पहले 22 मई 2019 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सीनियर एडवोकेट उमेश बोहरे ने कई दस्तावेजों के साथ एक जनहित याचिका में बताया था कि मरम्मत के लिए भेजी गयीं 20 लाख ईवीएम आयोग के पास वापस नहीं पहुंचीं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय ने 27 मार्च 2018 को भी ऐसी ही याचिका दायर की गयी थी। लेकिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कोइ जवाब नहीं दिया।

ईवीएम की खरीद से लेकर वोटों की गिनती तक हर जगह गड़बड़ियॉं हैं। चुनाव आयोग ने कोर्ट को अभी तक नहीं बताया कि ईवीएम मशीन की खरीद में आयोग क्या प्रक्रिया अपनाता है। कई बार ईवीएम मशीनें की स्पीड-पोस्ट से भी मंगाई जाती है। 2019 में जब लोक सभा चुनाव हुए तो 373 सीटें ऐसी थी जहां पर जो वोट डाले गए थे, उससे कहीं ज्यादा वोट ईवीएम की मशीनों में गिने गए। यूपी में मथुरा की सीट पर इस तरह का अंतर 9 हजार वोट का था। तमिलनाडु की 2 सीटों पर तो 18 हजार से ज्यादा अंतर आया था। बाकी सीटों पर भी 2 हजार से लेकर 15 हजार वोटों का तक अंतर था। इस गड़बड़ी का जवाब चुनाव आयोग ने आज तक नहीं दिया। अब ईवीएम मशीनों से चुनाव की सारी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। यदि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई, तो भारत की चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में है।

नवागत कलेक्टर ने पदभार ग्रहण करने के बाद की मीडिया से चर्चा

पूर्व कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम के स्थान्तरण के बाद घिरी सरकार

माही की गूंज, रतलाम।

कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम के सवालिया स्थान्तरण के बाद जिले के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उपस्थित मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए बेबाकी से पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जिले के विकास के विजन को साफ कर दिया।

नवागत कलेक्टर ने कहा कि, जिले में विकास कार्य और कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेंगे। उन्होने कहा कि, मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन होगा और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना उनका लक्ष्य रहेगा। रतलाम जिले में उनकी यह पहली पदस्थापना है, लेकिन आसपास के जिलों में वे पदस्थ रहे हैं और क्षेत्र से वह वाकिफ है। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। रतलाम के बारे में उन्होंने कहा कि, बहुत अच्छा जिला है। व्यावसायिक गतिविधियों की अपार संभावना है। जनप्रतिनिधियों के समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाएं आगे बढ़ाई जाएगी। आम जनता के हितों के कार्य होंगे।

माफियाओं को खुली चुनौती

माफियाओं पर कार्रवाई के सवाल पर नवागत कलेक्टर ने कहा कि, माफिया कोई भी हो वह समाज का दुश्मन है। उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी प्रकार के अवैध और काले धंदेबाज़ों को बख्शा नही जाएगा।

इस प्रकार से सोशल मीडिया पर पूर्व कलेक्टर के पक्ष में उतरे लोग, मुख्यमंत्री से किए सीधे सवाल।

पूर्व कलेक्टर की तारीफ

मात्र एक वर्ष के अंतराल में स्थानांतरित किये गए कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम की भी नवागत कलेक्टर ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि, जिले के पूर्व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले में विकास के कई कार्य शुरू किए हैं उनकी सोच विकास आधारित थी। पूर्व कलेक्टर द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यो को भी आगे बढ़ाया जाएगा।

नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी।

पूर्व कलेक्टर कुमार पुरषोतम।

कुमार पुरषोत्तम के स्थान्तरण के बाद सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से पूछे सीधे सवाल

रतलाम पूर्व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम अब ऐसे दूसरे कलेक्टर हो गए है जिनके तबादले के विरोध में आम आदमी मुख्यमंत्री से तबादला निरस्ती की गुहार लगा रहा है। 2004 में तत्कालीन समय में कलेक्टर रही, दिप्ती गौड़ मुखर्जी का तबादला होने पर विरोध हुआ था। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के तबादले के विरोध में ग्रामीण ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रो के युवाओं ने अपने ट्विटर एकाउंट पर सीएम को हेश टेग कर तबादला निरस्ती की मांग की है। शनिवार को राज्य शासन द्वारा रतलाम के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का तबादला खरगोन कर उनके स्थान पर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रतलाम कलेक्टर बनाये जाने के आदेश जारी किए थे। इन आदेश की सूचना जैसे ही रतलाम जिले में फैली उसके कुछ देर बाद बड़ी संख्या में युवाओ ने सोशियल मीडिया पर सरकार के इस आदेश का विरोध करना शुरू किया। ट्विटर पर अपने एकाउंट से युवाओ ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह को हैशटेग करते हुए तबादला निरस्त किये जाने की मांग की।

युवाओ द्वारा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के तबादले के विरोध के पीछे पुरुषोत्तम की कार्यप्रणाली है जिससे युवा और आमजन काफी खुश थे।

बता दे कि, जब रतलाम में कोरोना तेजी से बढ़ रहा था व नियंत्रण में नहीं आ रहा था, तब तत्कालीन गुना कलेक्टर कुमार को रतलाम में पदस्थ किया गया था। कुमार ने आते ही सख्त निर्णय लिए व एक पखवाड़े में कोरोना को तेजी से नियंत्रित किया। कलेक्टर के रुप में कुमार ने सख्त प्रशासक के रुप में अपनी पहचान बनाई। गुंडो के खिलाफ अभियान चलाया व अपराधियों के घर पर जेसीबी सख्ती से चलवाई। इसके अलावा अवैध खनन हो या कृषि विभाग में बीज की गड़बड़ी, सख्त निर्णय लिए। कॉलोनाइजरों पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू किया था, इस अभियान का आमजन ने स्वागत किया था। इसके अलावा गुंडे-बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाकर जेसीबी तक मकानों पर चलवा दी थी। बैठक में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते थे। इसके अलावा शहर से लेकर जिले मे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया व आमजन को राहत दी। जब कलेक्टर कुमार के तबादले की सूचना तेजी से वायरल हुई तो सोशल मीडिया में इसका जमकर विरोध होने लगा। लोगों ने लिखा रतलाम में अच्छे अधिकारी को हमेशा जल्दी हटा दिया जाता है। बता दे कि, कलेक्टर के रुप में कुमार को मात्र जिले में 370 दिन ही हुए थे।

बीड़ी खरीदने गए युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला, चार आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम।

चाकू बाज़ी के लिए मशहूर रतलाम शहर के एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है जिसमे एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। शहर के दिलीप नगर क्षेत्र में सोमवार रात एक युवक पर आरोपियों ने रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाशों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब युवक बीड़ी खरीदने गया था। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

स्टेशन रोड पुलिस थाना अंतर्गत घटना सोमवार रात 12 बजकर 15 मिनट दिलीपनगर स्थित महाकाल मेडिकल दुकान के सामने की है। घायल दिलीपनगर क्षेत्र का रहवासी 32 वर्षीय हिम्मत सिंह उर्फ बंटी है। हिम्मत सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी भरत पिता सत्यनारायण नायक, छोटू उर्फ़ समीर पिता फिरोज, लखन पिता राजेश जायसवाल एवं राहुल पिता बाबूलाल भाभर सभी निवासी बजरंगनगर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 307, 294 एवं 506 में प्रकरण पंजीबद्ध किया। घायल हिम्मत सिंह जिला अस्पताल में उपचाररत है। स्टेशन रोड टीआई किशोर पाटनवाला के अनुसार मामले में सभी आरोपीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गैस सिलेंडर ब्लास्ट, घर जलकर हुआ खाक

माही की गूंज, मंदसौर।

चंदवासा चौकी अंतर्गत समीप ग्राम खेर खेड़ी में दौलत राम के मकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे वो ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दौलत राम ने बताया कि उसके घर में देसी घी, खाद्य तेल, कपड़े, बिस्तर, पलंग, दालें व अन्य सामान के साथ फसल बेचकर लाए गए नगद 1 लाख 20 हजार की नकदी भी में जलकर नष्ट हो गई। इस ब्लास्ट से मकान का छतर, सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस घटाना से कुल मिलाकर तीन लाख के करीब नुकसानी हुई हैं। वहीं यह तो गनीमत रही की इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना रात डेढ़ बजे की बताई जा रही है, जिम्मेदारों को रात में सूचना दी गई घटना की लेकिन 10 घंटे तक जिम्मेदार घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे।

पूर्व मुख्यमंत्री को सफाई कर्मचारियों ने कराया समस्याओं से अवगत

माही की गुंज, शुजालपुर।

पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बुलाए जाने पर सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय महा सम्मेलन में शिरकत करने शाजापुर जिला अध्यक्ष अजय मोरटे अपनी पूरी टीम के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे। जहां कमलनाथ से मिलकर बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर व राजीव गांधी की तस्वीर भेंट कर शाजापुर जिले व शुजालपुर विधानसभा के समस्त सफाई कामगारों की और से कमलनाथ का सम्मान किया।

इस अवसर पर सफाई कामगारों की समस्याओं से अवगत कराने एवं उसका निराकरण कराने हेतु एक ज्ञापन भी सामूहिक रूप से कमलनाथ को सौंपा।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कमलनाथ ने कहा कि, सफाई कामगार लोग मेरे दिल में बसते हैं। मैं वाल्मीकि समाज से बहुत प्यार करता हूं और उनके देश की स्वछता के प्रति जज्बे को सलाम करता हूं। सफाई कर्मचारियों को मेरी सरकार आने पर सफाई सैनिक का नाम, दर्जा व सम्मान दिया जाएगा। मेरी सरकार आने पर आपकी हर मांग पूरी की जाएगी व वाल्मीकि समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएगी।

इस अवसर पर कमलनाथ के साथ साथ पूर्व मंत्री व विधायक भोपाल पीसी शर्मा, हुजूर के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा, पूर्व मंत्री व अनुसूचित जाती कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, सफाई कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौहान, कार्यवाहक अध्यक्ष देवकरण इंदौरा, राजस्थान से पधारे राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सचिव अनिल वर्मा, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव सिंह, चंद्र प्रभास शेखर, समस्त प्रकोष्ठ के प्रभारी जेपी धनोपिया, इंदौर से पधारे वरिष्ठ समाजसेवी महेश गोहर, मुकेश झांझोट पंछी, कार्यवाहक अध्यक्ष नरेंद्र बिलरवान, प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन बाली, भूरा पारोचे, गोपाल खरे, भोपाल जिला अध्यक्ष जितेंद्र बालूए सहित सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी गण व सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वागत भाषण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जयराज सिंह चौहान ने दिया व कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से देवकरण इंदौरा व अजय मोर्टे ने किया, आभार अर्जुन बाली ने व्यक्त किया।

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन प्रमाण-पत्र से सम्मानित हुए कलेक्टर श्री जैन

माही की गुंज, शाजापुर। जिले में विगत 23 मार्च को आयोजित हुए विशाल रक्तदान शिविर के सफल आयोजन पर गोल्डन बुक ऑफ रिकार्ड के द्वारा सम्मानित होने के बाद गत दिवस विश्व की प्रतिष्ठित संस्था वर्ल्ड बुक और रिकार्ड्स लंदन द्वारा इन्दौर में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों से आये विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन एवं रेडक्रॉस सोसायटी शाजापुर के नाम दर्ज रिकार्ड का प्रमाण पत्र, कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों श्याम जाजू, राकेश शुक्ला, जस्टिस रमेश गर्ग असम हाईकोर्ट, पूनम जेजलर प्रेसीडेंट डब्लूबीआर स्वीट्जरलैंड, मिस्टर जेजलर हेड ऑफ यूरोप स्वीट्जरलैंड द्वारा कलेक्टर दिनेश जैन को प्रदाय कर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सदस्य विश्व रिकॉर्ड एसोसिएशन अभिजीत सक्सेना, कथावाचक प्रदीप मिश्रा, विश्व विद्यालयों के कुलपतियों, राजनीतिक हस्तियों सहित कार्यक्रम में अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि, शाजापुर जिले में 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय शाजापुर पर कुल 22 स्थानों पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। जिसमें कुल 17 जिलो की ब्लड बैंक की टीमो द्वारा जिले में रक्त संग्रहण किया गया। जिसमें शाजापुर जिले में एक ही दिवस में जिले के नागरिको द्वारा कुल 2 हजार 887 यूनिट रक्तदान किया जाकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया।

कांग्रेसी प्रदेश में संघ का एजेंडा लागू नहीं होने देंगे- अरुण यादव

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के दौरे पर आए प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि, कांग्रेस के चिंतन शिविर में हमने हर वर्ग को लेकर चिंतन किया है। इसमें किसान, नौजवान, महिला सहित हर वर्ग की बात हुई है। इसके आलावा जो फासिस्टवादी ताकतें देश को खंड-खंड करना चाहती हैं, उन्हें ये पता नहीं कि ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका देश है। ये गांधी की विचारधारा से चलने वाला है। यहां फासिस्टवादी की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आगामी दो वर्षों तक कांग्रेस देश में काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो अभियान चलाएगी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती से होगी। इसमें कांग्रेस का बच्चा-बच्चा अपनी सहभागिता करेगा।

नहीं लागू होने देंगे आरएसएस का एजेंडा

यादव ने कहा कि, भाजपा के पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और लायन आर्डर की क्या स्थिति है। ऐसे में बीजेपी एक-दूसरे को आपस में लड़ाकर वोट बंटोरना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उन्हें इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, देश गांधी के विचारधारा पर चलने वाला देश कांग्रेसी प्रदेश में संघ का एजेंडा लागू नहीं होने देगी।

5 वर्ष सत्ता में रहते तो देते आरक्षण

यादव ने कहा कि, भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में झूठी रिपोर्ट पेश की है, इसके लिए उन्होंने कोई सर्वे नहीं करवाया है। अगर वो आरक्षण देना चाहती तो 20 साल से सत्ता में है, इतने दिन क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पांच साल कांग्रेस सत्ता में रहती तो बिल्कुल 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता।

राज्यसभा टिकट विवेक तन्खा को मिले

प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के चुनाव को लेकर अरुण यादव ने कहा कि, राज्यसभा के चुनाव का निर्णय दिल्ली से होता है। मैंने अपनी तरफ से और साथियों की तरफ से यह कहा है कि विवेक तन्खा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जरूरत दिल्ली में है, उनको प्रथम मौका मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पार्टी उन्हें जरूर मौका देगी।

यातायात पुलिसकर्मी की शह पर चल रहे बिना दस्तावेज के ट्रक

माही की गुंज, शुजालपुर। अजय राज केवट

प्रदेश सरकार द्वारा ओवरलोड वाहनों पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है लेकिन इसके बावजूद शहर में बिना रोक टोक बिना दस्तावेज के ओवरलोड वाहन बेलगाम दौड़ते हुए ट्रैफिक नियमों की धिजयां भी उड़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ओवरलोड वाहनों पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद शहर में बिना रोक टोक बिना दस्तावेज ओवरलोड वाहन बेलगाम दौड़ते हुए ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जिससे साफ है कि प्रशासन उनपर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो गया है। हमेशा ऐसे वाहनों से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई बार हादसे हो भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन मूकदशर्क बनकर बैठा है। शहरी क्षेत्र में सरेआम पुलिस के सामने से ओवरलोड वाहन गुजर जाते हैं।

दोगुने मुनाफे के लिए भरते हैं क्षमता से अधिक माल

शुजालपुर शहर वासियों का कहना है कि, ओवरलोड वाहन पुलिस की मिलीभगत से सरेआम चल रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस की आखों के सामने ये ओवरलोड वाहन बिना रोकटोक गुजरते है। पुलिस कागजात तक चेक नहीं करती।

सड़कें हो रही क्षतिग्रस्त, बढ़ रहे हादसे

ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिससे राहगीरों के अलावा दोपहिया वाहन चालकों को भी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि शहर के लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे ओवरलोड व बिना दस्तावेज के वाहनों पर नकेल कसी जाए। ऐसे वाहन लोगों की जान से खेल रहे हैं।

सुबह-शाम पहुंच जाते हैं कमाई के अड्डे पर

यातायात ट्रैफिक की हालत सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। लेकिन यहीं पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ट्रक वाहनों से वसूली करने में लगे रहते है। सुबह व शाम होते ही पुलिस वाले अपनी काली कमाई के अड्डे पर ही पहुंच जाते हैं। वही शुजालपुर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान बनाने के नाम पर जमकर अवैध वसूली में मस्त है। शुजालपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। शहर के बस स्टैंड पर कई बस समय से पहले बस स्टैंड पर लाकर खड़ी कर देते हैं जिससे लंबा जाम लग जाता है। पुलिस कर्मचारी इनको देख कर भी अनदेखा करते हैं।

लोगों ने कहा कि, हमने कई बार इन्हें जाकर कहा लेकिन इनकी सांठ-गांठ के चलते वह इनको कुछ नहीं कहते और जब बस संचालकों को कहा जाता है, तो वह बस स्टैंड पर दबंगई अपनी दिखाते हैं। शहर में आम लोग और ग्रामीणों के ऊपर पुलिस यातायात नियम उल्लंघन के चालान बनाती है, लेकिन अगर कोई प्रतिष्ठित धन संपन्न व्यक्ति इधर से निकलता है तो छोड़ दिया जाता है। वाहन चालकों को पुलिस इन्हें बेवजह रोक-टोक चालान वसूल ती है जिससे वह परेशान होते हैं। शहर में यातायात पुलिस की लापरवाही की वजह से हर चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है

वाहन जांच के नाम पर अवैध वसूली

शुजालपुर में कहीं दर्जनों ऑटो व ट्रक बिना दस्तावेज वह बिना परमिट फिटनेस टैक्स बीमा के फराटे से बेखौफ रोड पर आम जनता की जान लेकर दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन परिवहन विभाग ओर पुलिस विभाग के द्वारा इन ट्रक को के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की जा रही है ओर ये ट्रक बेखोफ होकर शुजालपुर में क्षमता से अधिक वजन भरकर शुजालपुर रहवासी लोगों की जान पर मोत का तांडव लिए फिर रहे हे व ओवर लोड भरकर लोगो की जान खतरे में डाल रहे है। शुजालपुर में लगभग दर्जनों ट्रक बिना किसी बीमा, फिटनेस, टैक्स, परमिट, पूरी तरह से कई सालो से खत्म हो चुके है बिना किसी दस्तावेज के दौड़ रहै है। जिन पर शुजालपुर प्रशासन पूरी तरह मेहरबान है। जिसकी वजह से इन ट्रको पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है आपको बता दें कि अवैध रूप से दौड़ रहे कई ट्रक के दस्तावेज कई सालो से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं जिसके बावजूद भी ट्रक संचालक अवैध रूप से दबंगई के बल पर ट्रको का संचालन करा रहे हैं और ओवरलोड वजन भर कर चला रहे हैं। जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

ट्राफिक पुलिस कर्मी को सूचना देने के बाद भी बने हुए हैं मूकदर्शक

ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को कई बार सूचना देने के बाद भी बिना दस्तावेज के वाहनों के गाड़ी नंबर देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे स्पष्ट होता है कि, कहीं न कहीं पुलिसकर्मी की मिलीभगत से ही लोगो की जान ले रहे हैं। जिसमे कई ना बालिक लडके जो कि उनकी उम्र भी कम है और न ही उनके पास कोई लाइसेंस है फिर भी वह ड्राइवरी कर रहे और आए दिन हादसे में आम जनता की जान ले रहे हैं।

जब इस बारे में आरटीओ से जानकारी लेना चाही तो जिम्मेदार अधिकारी ने फोन उठाना उचित नहीं समझा।

सीएम हेल्प लाईन में शिकायतों को लेकर 21 अधिकारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी

माही की गूंज, बड़वानी। कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने सीएम हेल्प लाईन में शिकायतों का निराकरण समय सीमा में नही करने पर 21 अधिकारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री आरके नवीन, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एनके प्रजापति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिता सिंगारे, जिला परिवहन अधिकारी नंदलाल गामड़, जिला परियोजना समन्वयक संजय सिंह तोमर, उप संचालक उद्यानिकी विजय सिंह, नर्मदा घाटी विकास के कार्यपालन यंत्री एस अछालिया, कनिष्ठ यंत्री अंजड़ कमल चैहान, वरिष्ठ कृषि अधिकारी ठीकरी एल पाटीदार, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री विनोद कुमार मण्डलोई, मुख्य नगर पालिका अधिकारी खेतिया यशवंत, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एसके अग्रवाल, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पाटी डॉ. देवेन्द्र वास्कले, जिला आबकारी अधिकारी दीपक अवस्थी, मुख्य कार्यपान अधिकारी सेंधवा राजेन्द्र कुमार दीक्षित, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ठीकरी लोकेन्द्र सोहनी, बीआरसी बड़वानी दिनेश खर्ते, तहसीलदार राजपुर श्रीमति सीमा कनेश, बड़वानी श्रीमति आशा परमार, अंजड़ भागीरथ वाखला, सेंधवा मनीष पाण्डेय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

प्रभारी मंत्री डंग ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

माही की गूंज, बड़वानी।

प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को बेहतर वितरण कर, सभी जगह पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में भी विद्युत विभाग के पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समयावधि अनुसार विद्युत वितरण हो, यदि कही पर विद्युत फाल्ट से अवरोध आता है तो उसे तत्काल दुरूस्त कर विद्युत व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाये। इस कार्य में यदि किसी पदाधिकारी की लापरवाही पाई जायेगी तो उस पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। बड़वानी जिले में कही पर भी विद्युत कटौती नही की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरदीपसिंह डंग ने मंगलवार को कलेक्टरेट सभागृह में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिये। बैठक में प्रभारी मंत्री के साथ राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी, लोकसभा सांसद गजेन्द्रसिंह पटेल, कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि, क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर विद्युत, पेयजल वितरण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाये। कही पर भी पीने के पानी की समस्या न आने पाये। यदि किसी क्षेत्र में जल स्त्रोत सूखने की स्थिति बनती है तो वहां प्रायवेट ट्यूबवेल को अधिग्रहित करके या पेयजल परिवहन करके भी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाई रखी जाये। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यो की भी समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके कार्यो की जानकारी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से दे। जिससे कार्यो में पारदर्शिता व गुणवत्ता बनी रहे। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए एनवीडीए तथा सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनओं का कार्य निर्धारित समय सीमा अनुसार पूर्ण हो, उनके कार्य की गुणवत्ता सही हो यह सुनिश्चित किया जाये। जिससे किसानों को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के तहत स्कूलो-आंगनवाड़ियो में जब तक सतत् जल वितरण व्यवस्था न हो जाये, तब तक उस ग्राम के जल जीवन मिशन के कार्य को पूर्ण नही माना जाये और ठेकेदार को उसका भुगतान न किया जाये। उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाला निःशुल्क अनाज नियमित रूप से मिल जाये यह सुनिश्चित किया जाये। साथ ही हितग्राहियो को 1 रुपये किलो मिलने वाला खाद्यान्न, प्रधानमंत्री की योजना के अतिरिक्त मिलना हैं इसकी जानकारी नियमित रूप से हितग्राहियों को दिलवाई जाये। जिससे कोई भी उचित मूल्य दुकान वाला हितग्राहियों के हितो का दुरूपयोग न करने पाये।

बिना बिल एवं अनुज्ञा के परिवहन किए गए गेहूं से लदे ट्रक जप्त

कृषि उपज मंडी को जिंदा करना जरूरी, दुकान-दुकान तुल रही अवैध रूप से कृषि उपज

माही की गूंज, भानपुरा।

नगर भानपुरा की कृषि उपज मंडी कहने को तो कृषि उपज मंडी है, परंतु किसानों के लिए यहां ना कोई सुविधा है और मैं ही नियंत्रण है, भानपुरा के व्यापारी कृषि उपज मंडी में माल नहीं के बराबर खरीदतें हैं। नगर की अनाज दुकानों पर जगह-जगह हर तरह की कृषि उपज खरीदी देखी जा सकती है। इसके पीछे राजनीतिक ईच्छाशक्ति की कमी होने एवं कृषि उपज मंडी के नियम कायदों से कहीं ऊपर नेताओं के मोबाइल पर आये आदेश के कारण भानपुरा की कृषि उपज मंडी कभी तरक्की नहीं कर पाई है। कभी कबार हिम्मत करके कृषि उपज मंडी के कर्मचारी मंडी से बाहर बिक रही कृषि उपज को पकड़ने की हिम्मत जुटा लेते हैं। बीती रात 17 मई 8:15 बजे औचक निरीक्षण के दौरान कृषि उपज मंडी भानपुरा के सचिव अशोक कुमार जैन के आदेश पर नियुक्त सहायक उपनरीक्षक मनीराम सुल्या एवं सुरक्षा गार्ड विनोद कुमार डांहिया ने बिना बील व अनुज्ञा के परिवहन हो रहे गेहूं से लदे ट्रक क्रमांक आरजे 33 जी ए 1564 को रोककर 300 बोरी गेहूं से लदे ट्रक से लगभग 200 क्विंटल गेहूं व ट्रक को अपने नियंत्रण में लेकर ग्राम पीपल्दा के 4 किसानों से खरीद कर लाया जा रहा 2100 रुपये प्रति क्विंटल की दर के गेहूं को जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख 20 हजार रुपए होती है एवं गेहूं क्रेता मनोज धाकड़ राणापुर कोटा एवं ट्रक चालक बालू उम्र 30 वर्ष पिता गोवर्धन लाल से समझौता शुल्क 5 हजार रुपए एवं देय निधि शुल्क 6 हजार 300 का 5 गुना 31500 तथा देय निधि शुल्क 840 रुपये कुल मिलाकर से 37 हजार 340 रुपये वसूल कर ट्रक एवं गेहूं फर्म के अधिकृत व्यक्ति को सौंपा।

उल्लेखनीय है कि, नगर भानपुरा में कृषि उपज मंडी पूरी तरह से समाप्त प्राय हो गई है,नगर की लगभग हर दुकान पर किसानों से कृषि उपज खरीदना आम बात है। यही नहीं शासन प्रशासन की लापरवाही से राशन की दुकानों पर बिकने वाला गरीबों की भोजन थाली का चावल भी भारी मात्रा में कहीं अनाज की दुकानों पर बिकता हुआ देखा जा सकता है। जो राशन की दुकानों पर चावल 1 से 3 रुपये में उपभोक्ताओं को दिया जाता है, वही चावल खुले बाजार में 16 से 17 रुपये में सरेआम बेंचकर इस गोरखधंधे को जारी रखे हुए हैं। सरकार गरीबों के हित में योजनाएं लाती है परंतु स्वयं उपभोक्ता व अनाज व्यापारी शासन को चूना लगाने में एवं अधिकारियों की अनदेखी के चलते छूट भैया नेताओं के दम पर इस धंधे को सिंचित कर शासन की योजनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं।

अमृत महोत्सव के अमृत सरोवर देंगे ठंडक

माही की गूंज, खरगोन।

आजादी के अमृत महोत्सव को सार्थक करते हुए मानवता के कल्याण के प्रति विषम तापमान में भी खरगोन जिले में अमृत सरोवर का निर्माण निर्बाध जारी है। यह जल राशियाँ जहां एक तरफ घटते भू-जल स्तर को पुनर्जीवित करेंगी वहीं मनरेगा से पोषित यह योजना सैकड़ों परिवारों के जीविकोपार्जन का साधन भी बन रही है। अमृत सरोवरों और जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिला पंचायत सीईओ श्री दिव्यांक सिंह हर दिन क्षेत्र में निरीक्षण कर कार्यों को गति दे रहे है। बुधवार को निरीक्षण के समय लोनारा स्थित गांव में स्थल तक चार पहिया वाहन जाने में असमर्थ रहा तो मोटरसाइकिल पर सवार होकर अमृत सरोवर का निरीक्षण करने पहुँचे।

जिला पंचायत सीईओ सिंह अपने निरीक्षण में मुख्य रूप से पड़ल पर ज्यादा फोकस कर रहे है। वो बताते है कि अब जमीन के अंदर हमें पानी स्टोर करके रखना ही होगा ताकि आपात समय में जमीन हमें पानी भी दे सकें। मनरेगा के परियोजना अधिकारी श्री श्याम रघुवंशी ने बताया कि गुरुवार को जिले में 9 हजार से अधिक श्रमिक केवल अमृत महोत्सव में कार्यरत रहे। जबकि पूरे जिले में अन्य कार्यों में कुल 54 हजार से अधिक मजदूर जल संरक्षण और भूमि संरक्षण जैसे कार्यों में जुटे हैं। 30 जून तक जिले में 107 अमृत सरोवर बनकर तैयार करना है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि एवं स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियो को किया लाभान्वित

माही की गूंज, बड़वानी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के बुधवार 18 मई को रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि व स्वामित्व योजना के हितग्राहियो को लाभान्वित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्टरेट सभागृह बड़वानी में भी उपस्थित किसानो एवं हितग्राहियों को दिखाया गया। इस दौरान कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, प्रदेश के केबिनेट मंत्री प्रेमसिंह पटेल के प्रतिनिधि भागीरथ कुशवाह, लोकसभा सांसद गजेन्द्रसिंह पटेल के प्रतिनिधि जगदीश धनगर, जुलवानिया के समाजसेवी दीपक शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान बंधु, हितग्राही उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के दौरान बड़वानी जिले के एक लाख 24 हजार किसानो के खाते में 24 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी जिले में मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि से लाभान्वित 5 किसानों को प्रतीकात्मक रूप से अंतरित राशि की प्रतिकृति भेंट की। वही स्वामित्व योजना के तहत जिले की पानसेमल, निवाली, ठीकरी तहसील के 2727 हितग्राहियो में से प्रतीकात्मक 5 हितग्राहियों को मिले भू-अधिकार पत्र सौंपे।

डॉ. मधुसूदन चौबे ने ध्यान प्रशिक्षण में प्राप्त किया प्रशंसापत्र

माही की गूंज, बड़वानी।

प्राचार्य डॉ. एनएल गुप्ता के मार्गदर्शन में संचालित किये जा रहे शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी के स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्षन प्रकोष्ठ के कॅरियर काउंसलर डॉ. मधुसूदन चौबे ने परमानंद इंस्टीट्यूट आफ योग साइंस एंड रिसर्च से सात दिवसीय मेडिटेशन प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा सक्रिय सहभागिता से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया।

कॅरियर काउंसलर डॉ. मधुसूदन चौबे ने बताया कि, उन्होंने यह अध्ययन इसलिए किया क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में योग एवं ध्यान का अध्यापन अनिवार्य रूप से किया जाना निश्चित किया गया है। इस अध्ययन से उन्हें युवाओं को योग और ध्यान से जोड़ने में सहायता मिलेगी। इस उपलब्धि पर प्राचार्य डॉ. एनएल गुप्ता, कॅरियर सेल के कार्यकर्तागण प्रीति गुलवानिया, किरण वर्मा, राहुल मालवीया, राहुल भंडोले, अंकित काग, राहुल वर्मा, राहुल सेन, नमन मालवीया, उमा फूलमाली, साक्षी परमार, वर्षा मुजाल्दे, जगमोहन गोले, नंदिता गोले, राधिका प्रजापति ने हर्ष व्यक्त किया और बधाई दी।

182 समितियों में खाद का पर्याप्त भंडारण

माही की गूंज, खरगोन।

वर्तमान में खरीफ 2022 के अंतर्गत आदान भण्डारण एवं वितरण प्रक्रियाधीन है। इसके अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन से संबद्ध 182 समितियों में उर्वरक का भण्डारण किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि, जिन किसानों ने संस्था से रबी 2021-22 के लिए ऋण प्राप्त किया है। वे अपने ऋण खातों का यथाशीघ्र नवीनीकरण करवा ले तथा उर्वरक प्राप्त करें। ऐसे कृषक जिनके संस्था में ऋण खाते नवीनीकरण हो चुके हैं वे भी संस्था में उपलब्ध रासायनिक खाद प्राप्त करें। इस संबंध में बैंक प्रबंध संचालक श्री राजेन्द्र आचार्च ने बताया कि रासायनिक खाद का उठाव कृषकों द्वारा कर लिया जाता है तो संस्थाओं के गोदाम रिक्त हो जाएंगे। साथ ही संस्थाएं पुनः कृषकों को वितरण के लिए उर्वरकों का पुनः भण्डारण कर लिया जाएगा। जिससे कि खरीफ सीजन में कृषकों को उर्वरकों की कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कृषक सदस्य शीघ्र उर्वरक प्राप्त कर शासन की योजना अनुसार शुन्य प्रतिशत ब्याज दर लाभ प्राप्त करें।

नल-जल योजना का तोहफा लेकर ग्रामों में पहुंचे कैबिनेट मंत्री श्री पटेल

माही की गूंज, बड़वानी।

निमाड़ में इस वक्त भीषण गर्मी वह भी उमस भरी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी में नमी होने के कारण शरीर से बहने वाला पसीना नहीं सूख पाता । जिसके कारण आमजन को हवा लगने के पश्चात भी ठंडक महसूस नहीं होती, जिससे वह बेचैन रहता है। ऐसी ही उमस भरी गर्मी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने ग्राम सोंदुल एवं बोकराटा पहुंचकर कई ग्रामों में बन चुकी जल जीवन मिशन योजना का लोकार्पण किया है। जिससे अब इन ग्रामों के वासियों को घर बैठे शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। प्रदेश के पशुपालन एवं सामाजिक कल्याण मंत्री एवं बड़वानी के विधायक प्रेम सिंह पटेल ने ग्राम सोंदुल में कल्याणपुरा, बोम्या, भवती, सोंदुल, कठोरा, पिछोडी, जामदाबेडी ग्रामों की तथा बोकराटा में पहुंच कर वहां पर बन चुकी जल जीवन मिशन योजना का लोकार्पण किया है। वहीं उन्होंने ग्राम सोंदुल में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भी लोकार्पण एवं प्राथमिक विद्यालय में बनने वाली बाउंड्रीवॉल तथा सीएमसी निर्माण का भूमिपूजन भी किया। इस दौरान श्री पटेल ने सोंदुल एवं बोकराटा में लगे किसान सम्मेलन में जहां सोसायटियो की तरफ से किसानों का सम्मान भी किया। वही इन ग्रामों में लगे जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के निर्देश भी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को मौके पर ही दिए हैं।

इस दौरान श्री पटेल ने उपस्थित ग्रामीणों से आह्वान किया कि नल जल योजना का संचालन बेहतर रूप से हो, इसके लिए वे समिति बनाकर उसका संचालन करें। और विद्युत देयक का भुगतान समय पर हो जाए, इसलिए निर्धारित पेयजल का शुल्क ग्राम पंचायत में जमा करवाएं। जिससे पेयजल वितरण में होने वाले विद्युत देयक का भुगतान नियमित रूप से होता रहे। शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, सिलेंडर, चूल्हा का भी वितरण किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाले निःशुल्क मूंग का भी प्रतीकात्मक रूप से वितरण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

समाजसेवी गांधी का निधन, लायंस क्लब ने करवाए नेत्रदान

माही की गूंज, बड़वानी।

प्रसिद्ध समाजसेवी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, सरस्वती शिशु मंदिर के संरक्षक, वाल्मिकी आश्रम के संरक्षक एवं लोकतंत्र सेनानी सरदार नानकसिंह गांधी का बड़वानी के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 90 वर्षीय नानकसिंह जी को अंतिम इच्छानुसार उनके परिजनों ने नेत्रदान की इच्छा जताई। इस पर उन्होंने लायंस क्लब बड़वानी सिटी के लायन राम जाट एवं लायन अनिल जोशी से संपर्क किया। लायन राम जाट द्वारा एमके इंटरनेशनल आई बैंक की डायरेक्टर डॉ. उमा झवंर से संपर्क कर कीट की व्यवस्था की एवं सरस्वती नेत्र चिकित्सालय के डॉ. ललित मालव को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचे एवं नेत्रदान की प्रक्रिया को संपन्न कर कार्निया को सॉल्यूशन में सुरक्षित कर आई बैंक भिजवाए। इस प्रक्रिया में लायंस क्लब के सचिन शर्मा, परिवार के गुरमीतसिंह गांधी, कंवलजीत सिंह गांधी, करतारसिंह गांधी, बलजीत सिंह गांधी, तेजिंदर सिंह गांधी, गुरमेल सिंह गांधी, सरबजीत सिंह गांधी, गुरदर्शन सिंह गांधी, मंजीत सिंह गांधी, स्वर संगम के कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल प्रबंधन का सराहनीय सहयोग रहा। लायन राम जाट ने बताया कि कोविड के कारण पिछले 2 वर्षो से नेत्रदान बंद थे। सूरदास जी की जयंती पर नानक सिंह की कार्निया से 4 नेत्रों को नवज्योति मिलेगी। गांधी निमाड़ क्षेत्र की एक प्रसिद्ध हस्ती थी उनके दुःखद निःधन से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है।

मिली सीटी स्केन मशीन की सौगात

माही की गूंज, अलीराजपुर।

म.प्र. के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी राजवधर्नसिंह दत्तीगांव, सांसद गुमानसिंह डामोर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनिता चौहान, विधायक जोबट श्रीमती सुलोचना रावत, विधायक अलीराजपुर क्षेत्रीय मुकेश पटेल, सांसद प्रतिनिधि नागरसिंह चौहान व माधोसिंह डावर ने पूजन कक्ष का फीता काटकर जिला चिकित्सालय अलीराजपुर में सीसी स्केन मशीन का लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री श्री दत्तीगांव ने सीटी स्कैन मशीन संचालन मरीजों को रिपोर्ट प्रदान किये जाने संबंधित जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संस्कृति जैन, नगर पालिका अध्यक्ष रितेश डावर, गणमान्यजन एवं सीएमएचओ डॉ. प्रकाश ढोके, सिविल सजर्न डॉ. सोनेरे सहित अन्य स्टॉफ सदस्य उपस्थित थे।

जिला गौरव दिवसः पूरे उत्साह के साथ निकाली गई गौरव यात्रा

जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कमर्चारी, व्यापारी, समाजसेवी, नागरिकगण रहे उपस्थित

माही की गूंज, अलीराजपुर।

अलीराजपुर जिला गौरव दिवस के तहत जिला मुख्यालय पर गौरव यात्रा का आयोजन हुआ। गौरव यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिता चौहान, कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संस्कृति जैन, सांसद प्रतिनिधि द्वय नागरसिंह चैहान व माधोसिंह डावर, नगर पालिका अलीराजपुर अध्यक्ष रितेश डावर, भाजपा जिलाध्यक्ष वकीलसिंह ठकराला सहित बडी संख्या में विभिन्न समाज के प्रतिनिधिगण, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, अधिकारी-कमर्चारीगण आदि सम्मिलित थे। बैंड बाजों के साथ गौरव यात्रा टंकी मैदान से प्रारंभ हुई। गौरव यात्रा में सम्मिलित सभी गणमान्यजन को व्यापारी संघ द्वारा सम्मान स्वरूप पगडी प्रदान की गई। गौरव यात्रा का विभिन्न जगह नागरिकगण ने शीतलपेय से स्वागत किया। गौरव यात्रा में सम्मिलित युवाओं ने जोरदार नृत्य और राष्ट्रभक्ति के नारे लगाकर यात्रा में उत्साह का संचार किया। यात्रा का बस स्टैंड, नीम चोक, झंडा चोक, रामदेव मदिर चैराहा, चांदपुर रोड होते हुए दाहोद नाका, टंटिया मामा चोराहे पर समापन हुआ। यात्रा के दौरान विभिन्न समाज संगठनों एवं व्यापारीगण ने अलीराजपुर जिला बनाए जाने के महत्व और जिला बनने के बाद से हुए विकास की बात कही।

दाहोद नाका पर गौरव यात्रा के समापन अवसर पर संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनिता चौहान ने कहा, अलीराजपुर जिला गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित आयोजनों ने पूरे आयोजन से जिलेभर को जोडने का कार्य किया।

कलेक्टर सिंह ने कहा, अलीराजपुर जिला गौरव दिवस के तहत पूरे एक सप्ताह तक जिले में कई आयोजन हुए। उक्त आयोजनों एवं खेल गतिविधियों से जिलेभर में प्रतिभाशाली बच्चों को आगे आने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, जिले में लगातार खेल गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से प्रतिभाओं को आगे लाने के प्रयास किये जाएंगें। उन्होंने कहा, अलीराजपुर जिला तेजी से विकास कर रहा है। जिला ने प्रदेश स्तर पर प्रगति के सौपानों को छू रहा है। प्रशासन जिलेवासियों तक शासन की विभिन्न योजनाओं और कायर्क्रमों को प्रभावी तरीक से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुलिस अधीक्षक सिंह ने कहा, जिले में सोशल पुलिसिंग के द्वारा आमजन के बीच सकारात्मक भाव पैदा करते हुए पुलिस लगातार सकारात्मक रूख के साथ जिलेवासियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। कायर्क्रम को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संस्कृति जैन ने संबोधित किया।

सांसद प्रतिनिधि नागरसिंह चैहान ने कहा, जिला बनने के साथ ही अलीराजपुर जिले में प्रगति के पथ पर तेज गति पकडी। यहां सडकों का जाल बिछाया गया। गांव-गांव बिजली पहुंच रही है। सिंचाई के साधन और परियोजनाएं लाए। स्वास्थ्य शिक्षाए सिंचाई के साधनों में जिला तेजी से आगे बढ रहा है।

सांसद प्रतिनिधि माधोसिंह डावर ने कहा, जिले में प्रकृति प्रचुर मात्रा है। यहां शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन से विकास नजर आता है।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर टंटिया मामा की प्रतिमा पर सभी गणमान्यजन ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। कायर्क्रम को किशोर शाह, संतोष थेपडिया, मुस्तान मर्चेंट, राजेश राठौर सहित अन्य समाजजनों ने संबोधित किया। अंत में आभार एसडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड ने माना।

सोशल मीडिया बना हिंसक जानकारी फैलाने का प्लेटफार्म

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

आजकल फेसबुक व अन्य सोशल मंचों पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, जो अभद्र, हिंसक, भ्रामक एवं राष्ट्र-विरोधी होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोग सक्रिय हैं अराजकता का माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन विडम्बना है कि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है। देश को तोड़ने की साजिशें एवं जनता के दिलों में दरारें डालने की कोशिशे। इन राष्ट्र-विरोधी उपक्रमों, नफरत फैलाने वाले भाषणों, तोड़मोड़ कर प्रस्तुत करने और भ्रामक सूचनाएं परोसने की जैसे होड़-सी लग गई है। यह तथ्य खुद फेसबुक और कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने अपने अध्ययन के बाद प्रकट किए हैं। हालांकि फेसबुक का दावा है कि वह किसी आपत्तिजनक सामग्री को प्रकाशित

नहीं करता, ऐसा करने वालों को तुरंत चेतावनी भेजता और सामग्री को रोक देता है।

प्रश्न यह है कि, फेसबुक की यह व्यवस्था यहां क्यों फैल हो गई...? कहीं खुद फेसबुक ऐसी नफरत की आंधी को सर्वव्यापी बनाने के लिये जिम्मेदार तो नहीं है...? कहने को फेसबुक सामाजिक मेल-जोल के मंच कहे जाते हैं, लेकिन इन मंचों पर जितनी राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक नफरत एवं द्वेष फैलाया जा रहा है, वह चिन्ताजनक हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक भारत में भ्रामक सूचना, नफ़रत वाले भाषण वाले कंटेंट को रोक नहीं पा रहा है। पर बड़ा सवाल है कि वह क्यों नहीं रोक पा रहा है...? क्या यह भारत के खिलाफ एक षडयंत्र का संकेत तो नहीं।

फ़ेसबुक के संस्थापक व सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने कहा था कि, फ़ेसबुक के इतिहास में भारत का बहुत महत्व है। फेसबुक जैसे सोशल मंचों का विकास इस उद्देश्य से किया गया था कि उनके जरिए लोग आपस में संपर्क बनाए, स्वस्थ और स्वतंत्र विचार प्रकट कर सकें और आपसी सौहार्द स्थापित कर सके।

चालक की लापरवाही से ट्रक प्रतीक्षालय के शेड में फंसा

माही की गूंज, आम्बुआ।

स्थानीय बस स्टैंड क्षेत्र में बालक कन्या प्राथमिक विद्यालय के बाहर बने यात्री प्रतीक्षालय के शेड में एक ट्रक चालक की लापरवाही से फंस जाने से राहगीरों को घंटों परेशानी उठानी पड़ी। भील सेना के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बघेल एवं कांग्रेस कार्यकर्ता सारिक खान द्वारा थाने पर सूचना दी जाने के बाद पुलिस विभाग ने मोर्चा संभाला। बार-बार लग रहे जाम को हटाने का प्रयास करते हुए यातायात बहाल किया बाद में ट्रक को थाने पर ले जाया गया।

आम्बुआ के मुर्गी बाजार क्षेत्र में स्थित बस स्टैंड पर आज 14 मई की सुबह 11 बजे जाम की स्थिति तब बन गई। जब एक ट्रक क्र. एमपी 13 जीए 4259 जिसमें वॉशिंग पाउडर तथा साबुन आदि भरा हुआ था, चालक की लापरवाही से बाजार की ओर जाते समय बालक कन्या प्राथमिक स्कूल के बाहर पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया द्वारा प्रदत्त यात्री प्रतीक्षालय (लोहे का) के शैड में ऐसा उलझ गया। ट्रक ऐसा उलझा कि न तो आगे जा सकता था और न ही पीछे जा सकता। ट्रक फस जाने के कारण आने-जाने वाले वाहनों की कतार लगने लगी तथा सड़क पर जाम लग गया। इसी बीच भील सेना के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बघेल तथा कांग्रेसी कार्यकर्ता सारिक खान वहां पहुंचे तथा जाम की स्थिति देखकर थाने पर सूचना दी। जहां से पुलिस विभाग का अमला बस स्टैंड पहुंचा तथा स्थिति नियंत्रण में लेकर यातायात सुचारू रूप से प्रारंभ कराया। ट्रक को निकालने हेतु प्रतीक्षालय के शेड को ऊंचा किया जाकर ट्रक निकाला गया तथा थाने पर ले जाकर यातायात में बाधा एवं संपत्ति को हानि आदि के मद्देनजर कानूनी कार्रवाई पर चालान काट कर छोड़ दिया गया।

स्मरण रहे कि, बाजार में दिन में कभी भी भारी वाहन जो कि व्यापारियों का इंदौर आदि स्थानों से किराना, हार्डवेयर, सीमेंट सरिया, कटलरी आदि अनेक प्रकार के सामान भरकर दिन में कभी भी आ जाते हैं तथा सामान उतारने में घंटों लग जाते हैं। जिस कारण कई बार आवागमन में परेशानी आम नागरिकों तथा वाहन चालकों को उठाना पड़ती है। भारी वाहनों के दिन में कस्बे में प्रवेश पर नागरिकों ने समाचार के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की मांग प्रशासन से की है ताकि दिन में बाजार में जाम की स्थिति न बने।

हाई स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर जवेरिया कुरैशी का किया सम्मान

माही की गूंज, अलीराजपुर।

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में जिले के बच्चों ने बडी उपलब्धि प्राप्त की है। हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में अलीराजपुर जिले में जुवेरिया कुरैशी पिता इसरार कुरैशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रभारी शहर काजी सैय्यद हनीफ़ मियां चिश्ती कादरी ने कहा, बच्चे आगे बढे और भविष्य के अनुसार अलग-अलग फिल्ड का चयन करें प्रोत्साहित करते हुए लगातार कडी मेहनत करते हुए आगे बढने के लिए प्रेरित किया। जवेरिया को पुष्पमाला से सम्मानित करते हुए मिठाई खिलाकर प्रमाण पत्र दिया गया।

इस अवसर पर प्रभारी शहर काजी सैयद हनीफ मियां, पार्षद साबीर बाबा, डाक्टर शकील सैख, मसुद अखतर एडवोकेट, सिराज तन्हा (सायर), जुनेद कुरेशी एडवोकेट, शाहीद मकरानी सदर जामा मस्जिद, सफी अजमेरी, मुसाईद शाह, अशरफ मास्टर, भुरु मकरानी, वहाब कुरेशी उपस्थित रहे।

दुर्घटनाओं के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई, प्रशासन की निष्क्रियता समझ से परे

माही की गूंज, आम्बुआ।

दिन प्रतिदिन समाचारों तथा समाचार पत्रों की सुर्खियों में सड़क दुर्घटनाएं छाई हुई रह रही है। इसके बावजूद जवाबदार प्रशासनिक विभाग की चुप्पी दुर्घटनाओं को और अधिक बढ़ाने में मदद करती नजर आ रही है। हाल ही में इस आशय का समाचार प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहा था मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी भी ओवरलोड वाहन यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं।

हम उल्लेख कर रहे हैं, क्षेत्र में यमदूत के वाहन की तरह सड़क पर सरपट दौड़ रहे चार पहिया (जीप आदि), तीन पहिया (ऑटो रिक्शा) वाहनों में क्षमता से अधिक अंदर व बाहर भरकर सवारियों की जान जोखिम डालने वाले अवैध रूप से चल रहे वाहनों के बारे में। ये वाहन दिन-प्रतिदिन हाट बाजार आने-जाने में अथवा वर्तमान में शादी-विवाह कार्यक्रम तथा शादी-विवाह होने के बाद अपनी क्षमता से अधिक सवारी ढोते हुए देखे जा सकते है। उससे कहीं अधिक वाहनों की छतों पर जिन में अवयस्क तथा बगैर लाइसेंसी वाहन चालक होते हैं। शादी-विवाह में रात भर डीजे की धुन पर नाचते शराब व ताड़ी का नशा करने के बाद नींद पता नशे की खुमारी में जब वाहन चलाते हैं तो नींद की जरा सी झपकीं दुर्घटना का कारण बन जाती है। हाल ही में झाबुआ जिले के रामा ग्राम से अलीराजपुर जिले के आजाद नगर में ऐसा ही एक ओवरलोड वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें 3 की मौत तो दो दर्जन के लगभग लोग (बच्चे व बड़े) घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं। ओवरलोड जीपें, टेंपो, तीन पहिया, ऑटो रिक्शा आदि इसके बावजूद आम्बुआ, आजाद नगर, अलीराजपुर, जोबट आदि अनेक स्थानों पर अभी भी बे खौंफ दोड़ रहे हैं। जवाबदार यह सब देख कर भी अनदेखी क्यों कर रहे हैं यह समझ से परे है। क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही इनकी कुंभकर्णी नींद टुटेगी...?

दो बाईकों में आमने-सामने की भिड़ंत में पांच घायल दो की मौत

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ थाना क्षेत्र के ग्राम सर्दी में आमने-सामने दो बाइकों में भिड़ंत होने से एक महिला सहित एक बच्चे की मृत्यु तथा 5 घायल हो गए।

दो मोटरसाइकिलों पर आ रहे ग्रामीणों की गाड़ियां आपस में भिड़ गई इसमें दोनों वाहनों पर सवार दूर जा गिरे। गिरने से बाइक पर बैठी महिला तथा बच्चे की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हैं। जिन्हें उपचार हेतु 108 की से स्वास्थ्य केंद्र अलीराजपुर ले जाया गया। बाइक चालक दोनों पुरुष भी घायल हो गए। आम्बुआ पुलिस द्वारा घटना की जानकारी प्राप्त कर विवेचना की जा रही है।

गेहूं के निर्यात पर लगी रोक, किसानों में आक्रोश

माही की गूंज, मंदसौर।

केंद्र सरकार के निर्णय ने गेहूं व्यापारियों के साथ ही किसानों और मंडी की व्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने से व्यापारी नाराज हैं। इसी नाराजगी को लेकर मंगलवार को व्यापारियों ने मंदसौर मंडी में गेहूं की नीलामी में भाग नहीं लिया। इस कारण जो किसान गेहूं लेकर आए थे उन्हें भारी परेशानियां हुई, अधिकांश किसान अपना गेहूं वापस घर लेकर चले गए। मंडी के अधिकारी दिनभर किसानों को यहीं समझाते रहे कि व्यापारियों ने नीलामी नहीं करने की पूर्व में ही सूचना दी थी। इस दौरान व्यापारियों ने सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर सरकार के निर्णय पर नाराजगी जताई। मांग की है कि हमारे द्वारा भेजे गए गेहूं से भरे ट्रक कांडला पोर्ट पर फंस गए हैं उन्हें खाली करवाया जाए। महासंघ के आव्हान पर 18 मई को व्यापारी मंडी में सभी उपज की नीलामी में भाग नहीं लिया।

गेहूं के अच्छे दाम मिलने से किसानों के साथ ही व्यापारी भी खुश थे। किसानों को गेहूं का भाव 2 हजार 400 रुपए क्विंटल तक मिल रहा था, लेकिन निर्यात पर रोक लगाए जाने से नाराज मंडी के व्यापारी संघों ने 17 मई को गेहूं नीलाम नहीं करने और 18 मई को सभी तरह की उपज नीलाम नहीं करने का निर्णय लिया। इस संबंध में लिखित में भी सूचना दी गई थी। मंगलवार को मंडी में कामकाज तो चला लेकिन व्यापारियों ने गेहूं की नीलामी नहीं की, इधर व्यापारियों के निर्णय की सूचना के संबंध में जानकारी नहीं होने से कई किसान मंडी में गेहूं लेकर आ चुके थे। यहां पर व्यापारियों की दो दिनों की हड़ताल के संबंध में जानकारी मिलने पर किसान भी खासे परेशान हुए। किसानों से चर्चा के बाद मंडी इंस्पेक्टर जगदीशचंद्र भांभर ने व्यापारियों से चर्चा की और कहा कि मंडी में गेहूं के जो ढेर पड़े है, उन्हें नीलाम कर ले। लेकिन व्यापारियों ने आगे माल नहीं जाने का हवाला देकर नीलामी के लिए असमर्थता जताई। इसके बाद अधिकारियों ने किसानों से कहा कि या तो गेहूं वापस ले जाए या 18 मई को क्या निर्णय होगा इसका इंतजार करे। अधिकांश किसान अपने गेहूं लेकर चले गए। किसानो का कहना था कि गांव से मंडी तक गेहूं लाने व वापस ले जाने में हजारों रुपए खर्च हुए है। व्यापारियों ने सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर कांडला पोर्ट में खड़े ट्रकों को खाली करवाने एवं गेहूं के निर्यात पर लगी रोक को हटाने की मांग की। इस पर सांसद सुधीर गुप्ता ने उच्च स्तर पर बात कर व्यापारियों की मांग का निराकरण करने का आश्वासन दिया।

अवैध रेत उत्खनन करने वाले खोद रहे नदी के किनारे

माही की गूंज, आम्बुआ।

नदियां रेत का भंडार समेटे हुए होती है मगर जब अधिक दोहन होने लगे तो नदियों में रेत कहां मिलेगी...? रेत का व्यापार करने वाले अब नदियों के किनारे खोदकर मिट्टी में दबी रेत निकालने के प्रयास में नदी के किनारों को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

वर्तमान में भवन निर्माण युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं। कही निजी तो कही ठेकेदारों द्वारा तो कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के भवन निर्मित हो रहे हैं। शासन-प्रशासन द्वारा क्षेत्र में रेत खदानें नीलाम नहीं की जाने के कारण लोग चोरी चुपके रेत परिवहन कर रहे हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में नदी, नालों में अब रेत न होकर कंकर पत्थर नजर आ रहे हैं। व्यवसाई अब नदी के किनारे जमा मिट्टी को खोदकर उसके नीचे दबी रेत निकाल कर ले जा रहे। जिसके कारण भविष्य में बरसात के समय नदी में बाढ़ की स्थिति होने पर ये किनारे धंस कर नदी को चौड़ा तो करेंगे ही साथ ही नदी किनारे स्थित उपजाऊ भूमि में भी कटाव कर भूमि को हानि पहुंचाएंगे। बाढ़ का पानी इस कटाव के कारण खेतों में घुसकर फसल आदि के साथ-साथ उपजाऊ मिट्टी को भी हानि पहुंचाएगा। इधर प्रशासन सड़क पर दौड़ रहे कुछ रेत परिवहन करने वाले वाहनों को तो पकड़ रहा है मगर वह कहां से भर कर ला रहे हैं यह नहीं देखा जा रहा है। प्रशासन यह नहीं देख रहा है कि अवैध उत्खनन से नदियों को कितना नुकसान हो रहा है। पर्यावरण एवं जलीय जीवो की कितनी हानि हो रही है। नदियों के किनारों को सुरक्षित रखने का प्रयास राजस्व एवं खनिज विभाग को करना बहुत जरूरी माना जा रहा है ताकि नदियां सुरक्षित रहकर मानव जीवन को संवार सकें।

सरकार की नाकामीः स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर या अब भी है अंधविश्वास का बोलबाला...?

माही की गूंज। संजय भटेवरा

झाबुआ। एक प्रचलित कहावत है कि, ''अपनी मां को डाकन कौन बताए'' यानि अपना सगा व्यक्ति यदि बिल्कुल गलत भी हो तो भी उसकी कोई गलती स्वीकार नहीं करता। यह वाक्या इन दिनों जिले में चल रही उथल-पुथल पर भी सटीक ही साबित हो रहा है। जिले के कई विभाग अपनी असफलताएं छुपाने के साथ इस कहावत को सही साबित कर रहे है। इन्ही में से एक विभाग है जिले का स्वास्थ्य विभाग। वैसे तो मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल आईएसओ प्रमाणित है, और जिले में कई सामुदायिक व प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। बावजूद इसके कई छोटे-मोटे मामलों में मरीजों की जान चली जाना कोई नई बात नहीं है। अगर किसी मामले में किसी मरीज की जान चली जाती है, तो जिले का स्वास्थ्य अमला जिले की आमजनता में अशिक्षा और अंधविश्वास को अपना हथियार बनाकर ''अपनी मां को डाकन बताने से बच जाता'' और बचे भी क्यों ना...? यह बड़े अफसोस की बात है कि, आधुनिकता के इस दौर में भी यह जिला, प्रदेश और देश में अत्यंत गरीब, अशिक्षित और पिछड़ा होने की श्रेणी में आता है। यहां अब भी एक बहुत बड़ा तबका अंधविश्वास में घिर कर अपनी जान गवां देता है। जबकि सरकार द्वारा हर बार इन आदिवासी पिछड़े जिलों में विकास के नाम पर खर्च की जाने वाली राशि करोड़ों में होती है। अब यह मुद्दा अलग है कि, अगर सरकार इतना रुपया खर्च करती है, तो वह जाता कहां है...? और इन रुपयों से किनका, कितना विकास अब तक हुआ है...? जबकि धरातल पर तो स्थिति ''ढाक के तीन पात'' ही है।

पिछले दिनों कालीदेवी थाना क्षेत्र में एक मामला देखने को मिला। जिसने जिले में प्रशासन की नाकामी और सरकार की हवाबाजी को उजागर कर दिया। जिले में फैले अंधविश्वास ने एक बार फिर एक नवविवाहिता की जान ले ली और सरकारी तंत्र मजाक बनकर रह गया। घटना कुछ ऐसी थी कि, कालीदेवी थाना अंतर्गत ग्राम पीलियाखदान में शादी समारोह में शामिल होने आई नवविवाहिता की उल्टी-दस्त से मौत हो गई। मृतका आशा पति जगदीश मैंड़ा निवासी ग्राम हत्यादेली, अपने पति जगदीश के साथ ग्राम पिपलियाखदान में एक शादी में शामिल होने आए थे और वे अपने काका ससुर मुन्ना सिंगाड़ के यहां रूके थे। आशा को अचानक उल्टी-दस्त होने लगे तो परिजनों ने गांव में ही बड़बाई, झाड़-फूंक करवाई लेकिन आशा की तबीयत सुधरने के बजाय और अधिक बिगडने़ लगी, जिसके बाद रिश्तेदार उसे रामा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान आशा की मौत हो गई। नवविवाहिता आशा की उपचार के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई व मर्ग कायम कर लाश को पीएम के लिए सुबह 10 बजे ले जाया गया। गंभीर मामला होने व महिला चिकित्सक यहा नहीं होने के कारण आशा के शव को दोपहर 2 बजे ट्रेक्टर-ट्राली की सहायता से झाबुआ जिला चिकित्सालय लाया गया। जिला चिकित्सालय में सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद शाम साढ़े 4 बजे शव का पोस्टमार्टम हो सका। उक्त मामले के साथ अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर जो सवाल उठते है वे बड़े गंभीर है। पहला यह कि, रामा-कालीदेवी आबादी के हिसाब से एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बावजूद इसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला चिकित्सक का न होना विडम्बना ही है। दूसरा यह कि, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक नहीं थी, तो शव को इतनी देर यहां क्यों रोका गया...? उसे पहले ही झाबुआ पीएम के लिए क्यों नहीं भेजा गया।

तीसरी सवाल यह कि, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामा में क्या कोई वाहन या एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, जो परिजनों को शव ट्रेक्टर-ट्राली में डालकर झाबुआ जिला चिकित्सालय लाना पड़ा...? यह सारे सवाल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के ढर्रे को ढकोसला ही साबित कर रहे है। जबकि इसके विपरीत जिले के स्वास्थ्य विभाग को कई तरह के तमगे और प्रमाण-पत्र देकर उसका महिमा मंडल किया जा रहा है। कागजी खानापुर्ति की यह सारी नकली उपलब्धियां जिले की गरीब आदिवासी जनता की जान से खिलवाड़ करने भर जैसा प्रतीत हो रहा है।

जिले में अब भी अंधविश्वास का ही बोलबाल चल रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद जिले में जागरूकता की अब भी कमी ही नजर आ रही है। ग्रामीण जनता को जागरूक करने के कई महान कार्य प्रशासन कागजी घोड़े दौड़ाकर कर चुका है और करोड़ों रुपये खर्च हो चुके है। प्रशासन के इस झूठे प्रयास को उपलब्धी बताकर कई प्रमाण-पत्र और अवार्ड भी हासिल किए जा चुके है। लेकिन इसकी हकीकत यह है कि, पश्चिमी मध्यप्रदेश के इस पिछड़े जिले के ग्रामीणों में अब भी अंधविश्वास कूट-कूट कर भरा हुआ है। चाहे जैसी बीमारी हो ग्रामीण सरकारी अस्पतालों की तरफ मुंह करने के पहले मरीज को लेकर अपने क्षेत्र के बड़वे के पास पहुंचकर झाड-फुक करवाते है। बड़वे का ''धूल में ले चलाना'' सिद्ध हो गया तो ठीक, वरना मरीज मौत के मुहाने तक पहुंच जाता और फिर अंतिम क्षणों में अस्पताल की ओर दौड़ लगाई जाती। यहां भी स्थिति ''लगा तो तीर नहीं तो तुक्का'' वाली ही रहती है। बच गया तो ठीक, वरना मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। जब-जब इस तरह के मामले सामने आते है, तो ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव और प्रशासन की नाकामी दोनों ही खुलकर सामने आ जाते। जब तक प्रशासन अपना कर्तव्य, निष्ठा से नहीं निभाएगा तब तक ऐसी ही आशाओं की मौत अंधविश्वास और इलाज के अभाव में होती रहेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने राज्यमंत्री परमार की बहू को दी श्रद्धांजलि

माही की गुंज, शाजापुर।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को शाजापुर जिले के ग्राम पोचानेर आकर स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री व झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री इंदरसिंह परमार की बहू स्व. श्रीमती सविता परमार के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अश्रुपुरित राज्यमंत्री श्री परमार की पीठ पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ सासंद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एवं भाजपा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने भी राज्यमंत्री श्री परमार की बहू श्रीमती सविता परमार के चित्र पर पुष्पांजली अर्पित करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री श्री चौहान ग्राम बेरछादातार भी पहुंचकर शाजापुर जिले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष स्व. नरेन्द्र सिंह बैस के पिता पीरसिंह बैस, पुत्र दिग्विजय सिंह बैस, भाई महेन्द्रसिंह बैस, महिपाल सिंह बैस एवं मनोहर सिंह बैस सहित परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर स्वर्गीय नरेन्द्र सिंह बैस के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान शुजालपुर भी पहुंचे। यहां उन्होंने ऊर्जा विकास निगम पूर्व अध्यक्ष विजेन्द्र सिंह सिसोदिया के निवास पर जाकर उनके पौत्र स्वर्गीय भानुप्रताप सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोक संतप्त विजेन्द्र सिंह सिसोदिया एवं उनके परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। जिसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष संदीप सणस के निवास पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय लक्ष्मणराव सणस (अप्पा जी) के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने संदीप सणस की माता जी श्रीमती शकुंतला से भी मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की।

इस दौरान सासंद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा, भाजपा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी बृजेन्द्र सिंह यादव, क्षेत्रीय सांसद महेन्द्रसिंह सोलंकी, अम्बाराम कराड़ा एवं विजयसिंह बैस भी साथ में थे।

हुई बाईक चौरी

माही की गूंज,खवासा।

राजवाड़ा चौक खवासा में शनिवार-रविवार की मध्य रात्रि में चोरो ने संदीप महेंद्र वागरेचा के घर के बाहर रोज की तरह हैंडल लॉक लगी हुई खड़ी हीरो की सुपर स्प्लेनेडर बाईक एमपी 45 एमएस 2738 चोरो ने चोरी कर पुलिस को चुनौती दी है। जब सुबह संदीप वागरेचा ने अपनी बाईक को घर के बहार खड़ी हुई नहीं दिखी, तो वो अचंभित हो गए और उन्होंने आस-पास में जाकर गाड़ी की तलाश भी की, लेकिन गाड़ी का कोई पता नहीं लगने पर उन्होंने सुबह बाईक चोरी हो जाने की सुचना पुलिस चौकी पर जा कर दर्ज करवाई।

जय आदिवासी संगठन (जयस) में हुई रार से आगामी चुनाव के नतीजे प्रभावित होने की उम्मीद कम

जिले में आखिर किसके नियंत्रण में जयस संगठन

माही की गूंज, झाबुआ।

आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के नाम पर आदिवासी शिक्षित वर्ग के द्वारा एक बड़ा संगठन जय आदिवासी संगठन ,(जयस) खड़ा किया गया। आदिवासी दिवस को धूमधाम से मना कर राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक जमीन आदिवासी क्षेत्रों में हिला दी। जयस की एंट्री के बाद दोनों बड़ी पार्टीयो को आदिवासी सीटो पर काम करना पड़ा और आज भी जारी है। 2018 के चुनाव में कई सीटों पर अपना प्रभाव भी साबित किया। कांग्रेस की टिकिट पर जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा विधानसभा तक पहुच गए। जमीन स्तर पर खड़ी हुई टीम को स्थानीय चुनाव का इंतजार था, लेकिन सरकार की अदला-बदली और कोविड-19 की वजह से चुनाव लगभग 3 वर्षो से टल गये। इस बीच मजबूती से खड़े हुए संगठन में अलग-अलग भागो में प्रदेश स्तर से बटना शुरू हुआ जो अब जिला स्तर पर आकर संगठन को कमजोर कर गया। जिसका सीधा-सीधा प्रभाव आने वाले स्थानीय चुनावों में देखने को मिलेगा। फिलहाल संगठन मजबूत है लेकिन नेतृत्व और नेटवर्क की कमी साफ देखी जा रही है, जिसका फायदा बड़े दल उठा रहे है।

जयस के दो जिलाध्यक्ष और एक प्रभारी, कई कार्यकर्ताओ द्वारा बड़े पद के होते है दावे

अभी कुछ दिन पूर्व खबर आई थी कि, पूर्व जयस जिलाध्यक्ष विजय डामोर को दोबारा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया और कुछ दिन बाद एक और घोषणा के साथ खबर आती है कि, जयस जिलाध्यक्ष रमेश कटारा और जयस जिला प्रभारी कांतिलाल गरवाल को नियुक्त किया गया। दो-दो जिलाध्यक्ष और एक जिला प्रभारी की नियुक्ति के बाद जयस कार्यकर्ता दो भागों में बटते दिखाई दे रहे है और संगठन के दोनों जिलाध्यक्ष से चर्चा करने पर असली और नकली संगठन तक बात सामने आती है। कार्यकर्ता किसके साथ काम करना चाहते है ये भी साफ नही है। जिस क्षेत्र में जिसको काम पड़ता है, कार्यकर्ता उसे ही अपना जिलाध्यक्ष मानकर कार्य करना शुरू कर काम निकलवा लेता है। कई कार्यकर्ता अलग-अलग संगठन में पद होने के दावे कर रहे है। वही प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी भी दोनों संगठन के जिलाध्यक्ष के साथ अलग-अलग नजर आते है।

विजय डामोर जिलाध्यक्ष जयस

रमेश कटारा जिलाध्यक्ष जयस

कांतिलाल गरवाल जिला प्रभारी जयस

स्थानीय चुनाव में भूमिका कमजोर होने की आशंका

एक बार फिर स्थानीय चुनाव की खुसबुसाहट शुरू हो गई है लेकिन दो से तीन और चार भागों तक बटी हुई जयस की उपस्थिति इन चुनावों में कमजोर साबित होगी, इसकी आशंका है। इस प्रकार से बटी हुई जयस मैदान में उतरी तो कही न कही इसका खामियाजा संगठन को ही भविष्य में भुगतना पड़ेगा, जो वर्तमान में जितना प्रभाव स्थानीय राजनीति में नही छोड़ पाएंगे माना जा सकता है। वर्तमान में जयस संगठन पर प्रभावी रूप से किसका नियंत्रण है ये कह पाना मुश्किल है।

सिर्वी समाज के आईमाता प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक कार्यक्रम में समाज सेवियो ने दिया बड़ा योगदान

कार्यक्रम की भव्यता ओर सफलता को देखकर नगर परिषद अध्यक्ष मनोहर लाल भटेवरा ने गौरव दिवस के रुप में मनाने की घोषणा

माही की गूंज पेटलावद, राकेश गेहलोत

नगर में निवासरत एक बड़े समुदाय सिर्वी समाज के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय आई माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की ऐतिहासिक सफलता के बाद आयोजन को हर कोई सराह रहा है। आयोजन समिती द्वारा आयोजन के एक-एक कार्यक्रम को इतनी भव्यता से पूर्ण किया की नगर का हर वर्ग अपने आपको आयोजन से जुड़ने से नही रोक सका और हर किसी ने बढ़-चढ़ के आयोजन में अपनी सहभागिता की। आयोजन की भव्यता का पता इसी बात चलता है कि, पूरे वर्ष भर अलग-अलग बैनर नगर में बड़े-बड़े और एतिहासिक आयोजन होते आये है, लेकिन किसी भी आयोजन को गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का सम्मान नही मिला। लेकिन आईमाता प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को नगर परिषद अध्यक्ष मनोहर लाल भटेवरा ने गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर आयोजन को सफलता के शिखर पर पहुचा दिया।

छोटे बन करगए बड़ा काम, लाखो का खर्च कर समाज को किया प्रेरित

यू तो इस भव्य आयोजन में पूरे सिर्वी समाज़ के एक-एक परिवार ने तन-मन-धन से सहयोग किया। लेकिन दो साल के चल रहे मन्दिर निर्माण के कार्य को प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के साथ पूर्ण करना सिर्वी समाज के लिए बडी चुनोती था। ऐसे में समाज के कुछ वरिष्ठ लोगो ने इस चुनौती को अपनी घोषणा से इस बड़ी चुनौती को मामूली बना दिया।

भोजन व्यवस्था का जिम्मा लिया गंगाराम परमार ने

12 मई से 16 मई 5 दिनों तक हुए आयोजन में सबसे बडी चुनौती भोजन प्रसादी की थी, जिसका खर्च लगभग 40 लाख तक होना था। नगर के सिर्वी समाज़ के वरिष्ठ समाजसेवी गंगाराम परमार एवं परिवार द्वारा इस पूरे आयोजन में भोजन पर होने वाले समस्त खर्च जिम्मा अपने सर पर लिया। 5 दिन तक चले इस भव्य आयोजन में 50 से 55 हजार से अधिक लोगों ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया, हर दिन भोजन में एक मिठाई दी गई। इस पूरे आयोजन में होने वाला सबसे बड़ा खर्च समाजसेवी गंगाराम परमार द्वारा भोजन व्यवस्था पर 40 से 45 लाख का खर्च किया गया, गंगाराम परमार के इस कार्य की न केवल समाज बल्कि हर वर्ग प्रशंसा कर रहा है ।

भोजन प्रसादी के लाभार्थी समाजसेवी गंगाराम परमार।

मन्दिर शिखर के लाभार्थी समाजसेवी कोलाजी मोड़ाजी पडियार।

नाश्ते के लाभार्थी समाजसेवी रामा परमार।

आयोजन को गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने के घोषणा करने वाले नगर परिषद अध्यक्ष मनोहर लाल भटेवरा।

आयोजन में नि :शुल्क जल सेवा के लाभार्थी समाजसेवी बाबूलाल काग।

शिखर के लिए दिए 15 लाख

दो साल से अधिक, दो करोड़ से अधिक की लागत से तैयार आई माता मंदिर में सिर्वी समाज के लोगो ने बढ़-चढ कर बोली लगाकर लाभ लिया। मन्दिर पर चढ़ने वाले शिखर के लिए नगर के वरिष्ठ सिर्वी समाज के समाजसेवी कोलाजी मोड़ाजी पडियार ने 15 लाख रुपये दिए। मन्दिर निर्माण के दौरान

किसी भी प्रकार की राशि को आवश्यक होने पर समिति को कभी निराश नही किया और सहयोग किया।

नाश्ते का खर्च का लाभ रामा परमार ने लिया

भोजन की व्यवस्था के साथ आयोजन में शामिल होने वाले समाजजन ,अतिथियों के नाश्ते की व्यवस्था भी समिति के सामने बड़ी चुनौती थी। जिसे नगर के वरिष्ठ समाजसेवी रामा परमार ने अपनी और से पूर्ण खर्च करने की घोषणा कर, आयोजन में 5 दिन के नाश्ते पर लगभग 8 से 10 लाख रुपये खर्च किये और आयोजन समिति को सहयोग कर सेवा का लाभ लिया।

जल व्यवस्था का जिम्मा संभाला बाबूलाल काग ने

भीषण गर्मी के बीच हुए, इस भव्य आयोजन में जगह-जगह पानी की व्यवस्था करना बड़ा काम था। समाजसेवी बाबूलाल काग जो कि, खुद का आरोवाटर प्लांट चलाते है, इस धार्मिक आयोजन में मन्दिर स्थल से लेकर भोजन स्थल तक और कई चयनित स्थानों पर पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था नि:शुल्क की और प्रतिदिन 300 से 350 पानी की केन और अंतिम दिन लगभग 500 केन इनके द्वारा सही समय पर खुद के निजी वाहन और निजी कर्मचारियों से करवाया। इतनी बड़े आयोजन में पानी की कोई कमी नही होने दी। समाज़ के ऐसे सच्चे समाजसेवीयो की वजह से ये भव्य आयोजन सफलता के शिखर को छू सका। कई ऐसे समाज जन भी है जिन्होंने इस धर्म की गंगा में निस्वार्थ भाव से डुबकी लगाई।

अध्यक्ष की घोषणा ने आयोजन की भव्यता को लगाए चार चांद

पांच दिन तक चले ऐतिहासिक आयोजन के अंतिम दिन नगर परिषद के अध्यक्ष मनोहर लाल भटेवरा ने जब इस भव्य आयोजन को गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तो सकल सिर्वी समाज की मानो दो साल की तपस्या सिद्ध हो गई। मध्यप्रदेश के सामाजिक एवं न्याय विभाग के अंतर्गत सभी नगर परिषद को अधिकार है, जो स्थानीय स्तर पर होने वाले किसी एक बड़े आयोजन को गौरव दिवस के रूप में मना सकते है, जिसके लिए शासन द्वारा राशि आबंटन की जाती है। अध्यक्ष की घोषणा के बाद अब प्रतिवर्ष 16 मई को आईमाता प्रकोटोत्सव पूरे नगर में गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसका खर्च भी नगर परिषद उठाएगी। आयोजन अपने आप मे नगर के इतिहास में इतना भव्य था कि, नगर परिषद अध्यक्ष की इस घोषणा को हर समाज ने खुले मन से स्वीकार किया।

अध्यक्ष मनोहरलाल भटेवरा ने बताया कि, अगले वर्ष के लिए आयोजन की रूप रेखा तैयार की जाएगी और गौरव दिवस के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422